कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

क्रिकेट विश्वकप 2011

भारत के विश्वविजेता बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई।

नितिन गडकरी
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

कवर स्टोरी

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर विशेष........ 7
असम : विजन डाक्यूमेन्ट का विमोचन........ 10

भाजपा स्थापना दिवस

नई दिल्ली........ 14
मध्यप्रदेश........ 29
भाजपा का राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष 6 अप्रैल से........ 16

लेख

भारत की गिरती साख
cychj iqt........ 17
देशहित में हो भ्रष्टाचार–मुक्त राह
IR;iky........ 21
मनमोहन सिंह का नो–बाल, शून्य पर हुये आऊट
vEck pj.k of'k"B-........ 25
डॉ. अम्बेडकर जयंती पर विशेष
Mk- f'ko 'kfDr cDlh........ 27

अन्य

मेरठ (उ.प्र.): महासंग्राम रैली........ 6
असम : विजन डाक्यूमेन्ट का विमोचन........ 10
रांची (झारखंड): विशाल जनसभा........ 12
भाजपा बिहार प्रदेश कार्यसमिति बैठक........ 18

संपादक के नाम पत्र...

'कमल संदेश' पाक्षिक पत्रिका का फरवरी 16–28, 2011 अंक का संपादकीय ''भ्रष्टाचार में कीर्तिमान बना रहा यूपीए'' पढ़ा। निश्चित रूप से केन्द्र सरकार द्वारा घोटाले–दर–घोटाले भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। जनहित एवं आमजन के कल्याण का कोई भाव केन्द्र की सरकार में नहीं दिखाई देता। इन घोटालों एवं भ्रष्टाचार के उजागर होने के उपरांत प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य कि ''मैं मजबूर हूं'' अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। यदि इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति जनता के प्रति इतने पवित्र कर्त्तव्य के निर्वहन में होने वाली गंभीर त्रुटियों के लिये ऐसे बयान दे तो यह अत्यंत ही शर्मनाक स्थिति है। ऐसी सरकार और भ्रष्ट मंत्रिमण्डल लोकतंत्र के लिये भी सर्वथा घातक है।

i:d t ok/kokuh
एडव्होकेट एवं विधि व्याख्याता
श्री ज्ञाननिवास, 25–ए, राधा नगर
कॉलोनी, इन्दौर

किकेट विश्व कप 2011

अट्ठाईस साल बाद फिर बना भारत विश्वविजेता

भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में श्रीलंका को छह विकेट से हराकर देश को गौरवशाली उपलब्धि दिलाई। भारत ने 28 साल बाद दूसरी बार विश्व कप जीता है। इससे पहले कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने इंग्लैंड में हुए 1983 के विश्व कप में वेस्टइंडीज को हराकर जीत हासिल की थी। श्री महेन्द्र सिंह धोनी फाइनल के 'मैन ऑफ द मैच' तथा श्री युवराज सिंह टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने।

संवत् नववर्ष पर शुभकामनाएं

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 4 अप्रैल 2011 को भारतीय नव संवत्सर, गुढ़ी पाडवा, उगाडी और चेटी चण्ड के शुभावसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

श्री नितिन गडकरी ने आशा प्रकट कि की यह नव वर्ष हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसन्नता और शांति का संदेश लेकर आएगा।

हमें लिखें..

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी–66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003
ई–मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

भ्रष्टाचार के बढ़ते अभिशाप को मिटायें

समाधकीय

Vkज लोग सरकार को भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा देख रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई है कि न केवल सरकार भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में लिप्त होती जा रही है, बल्कि वह इसके लिए किसी तरह का ठोस उपाय करने से भी दूर भाग रही है, जिम्मेदारी उठाना तो दूर की बात है। केन्द्र में कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है और शासन में फैले भ्रष्टाचार से उसने आंखें मूंद रखी हैं। इससे सरकार का कामकाज कुप्रभावित हो रहा है। सरकार का कामकाज कुप्रभावित होने के पीछे कांग्रेस पार्टी के वे भ्रष्ट आपराधिक तत्व हैं, जिन्हें पार्टी में संरक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री अपने को 'मजबूर' बता कर तथ्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं जब वे अपने सहयोगी दलों पर दोष मढ़ कर यह कहते हैं कि गठबंधन सरकार चलाने में आप मेरी 'मजबूरी' समझिए, जबकि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस संस्कृति ही भ्रष्टाचार पर टिकी है।

कांग्रेस–नीत यूपीए अपने पहले शासनावधि के दौरान बेनकाब हो गई थी, जब इस ने सांसदों को घूस देकर गैर–कानूनी साधनों से विश्वासमत के दौरान अपनी सरकार बचाने की कोशिश की और पूरी संसदीय लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया था। हालांकि लोगों ने हाल के राष्ट्रमण्डल खेलों की लूट, आदर्श सोसाइटी घोटाला, देवास करार और 2जी स्पेक्ट्रम घपला एवं कुछ अन्य प्रकार के घोटालों को देखा है, फिर भी न जाने यह कैसी सरकार है कि इन घोटालों में लिप्त किसी भी अपराधी को सजा देने के लिए कोई भी कारगर और विश्वसनीय कदम उठाने की उसे फिक्र तक नहीं है। अब तो शुंगलु समिति की रिपोर्ट भी आ गई है, परन्तु क्या हुआ? रिपोर्ट में शीला दीक्षित और सुरेश कलमाड़ी पर अनेक आक्षेप होने के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। उल्टे, सरकार इन अपराधियों, घोटालेबाजों और देश का पैसा लूटने वालों के साथ सांठ–गांठ करती नजर आ रही है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप कर सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी ताकि सरकार पर कार्यवाही करने के लिए दबाव बने। पीजे थॉमस का केन्द्रीय आयुक्त के रूप में नियुक्ति तथा उनका हटाया जाना इसका एक उदाहरण है।

इसी तरह लोकायुक्त द्वारा दिल्ली सरकार के एक मंत्री के खिलाफ टिप्पणी के बावजूद वे आज भी मुख्यमंत्री के खुले संरक्षण में निर्लज्जतापूर्वक पद पर बने हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को, कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार द्वारा गठित शुंगलू समिति ने खूब फटकारा है और उन्हें राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए अनियमितताएं बरतने और अकूत धन लुटाने का दोषी पाया है, परन्तु वह आज भी अपने पद पर बनी हुई हैं। सार्वजनिक जीवन में कहीं नैतिकता का स्थान ही नहीं रह गया है। इन सभी मामलों पर श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री ने गहरी चुप्पी साध कर अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी दोषियों को संरक्षण देना अपना कर्त्तव्य समझा हुआ है। और दूसरी तरफ, महंगाई रूकने का नाम नहीं ले रही है और कांग्रेस की केन्द्र सरकार देश को कुशासन, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन की लूट के युग में धकेलने में जुटी पड़ी है।

कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार द्वारा कोई भी विश्वसनीय कदम नहीं उठाने के फलस्वरूप पूरी की पूरी राजनैतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है। देश की आंखों में धूल झोंक कर सरकार आधे–अधूरे कदम उठा कर लोगों को अब बेवकूफ नहीं बना सकती है। लोगों ने अब सरकार की चालों को समझना शुरू कर दिया है तथा अब वह और अधिक गुमराह नहीं हो सकते। यही कारण है कि आज श्री सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे भ्रष्टाचार के विरूद्ध अनशन पर बैठकर

पूरे देश का समर्थन पा रहे है, और अब यह एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। श्री अण्णा हजारे को हमारा और पूरे देश का अभिनन्दन है कि उन्होंने जन लोकपाल विधेयक और भ्रष्टाचार को महत्वपूर्ण विषय बना कर आंदोलन छेड़ा है। वह बधाई के पात्र हैं और उनके इस पावन कृत्य को सभी का समर्थन मिलना चाहिए और मिला भी है। दूसरी तरफ, प्रत्येक राजनीतिक दल को इस तरह के पहल को मिल रहे जन समर्थन को समझना चाहिए और नैतिक मानदण्डों को अपनाना चाहिए जिसकी आज लोग उनसे अपेक्षा कर रहे हैं।

भारत के अपने सामाजिक आचरण और परम्पराएं सदैव ही सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मानदण्डों एवं नीतिगत मूल्यों पर टिके रहे हैं। भारत की परम्परा सदैव ही ऋषियों और महात्माओं को पूजती रही है, समाज में राजा–महाराजाओं को सदा ही दूसरे स्थान पर रखा गया है। हमें 'त्यागी' और 'भोगी' के बीच का अंतर मालूम है, अतः हम सदा ही सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों और नैतिक आचरणों के उच्च सिद्धांतों के पथ पर चलना ही अपना धर्म समझते रहे हैं। अब समय आ गया है जबकि भ्रष्टाचार के बढ़ते अभिशाप को रोकने के लिए कारगर और विश्वसनीय कदम उठाना नितांत आवश्यक है। ■

प्रदेश के विकास के लिए भाजपा एकमात्र विकल्प : नितिन गडकरी

गत 9 अप्रैल को मेरठ स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित महासंग्राम रैली में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस, सपा और बसपा को एक ही थाली का चट्टा–बट्टा कहकर प्रदेश के विकास के लिए भाजपा को ही मूल विकल्प बताया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने तो राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है, अब जनता की बारी है। वह रामराज का सपना प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवा कर साकार करे। जातिवाद और साम्प्रदायिकता की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है। जनता विकास की राजनीति का समर्थन करे। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर श्री गडकरी ने कांग्रेस और बसपा को निशाने पर लिया।

उन्होंने कहा, दिल्ली से लखनऊ तक माया कमाने का काम चल रहा है, लक्ष्मी दर्शन में सभी व्यस्त हैं। जिस प्रदेश के सात मंत्री भ्रष्टाचार और तीन मंत्री बलात्कार–हत्या के आरोप में पद से हटाए गए, ऐसे में प्रदेश के विकास की कल्पना भी बेमानी है। गडकरी ने कॉमनवेल्थ, 2जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी घोटाले के लिए कांग्रेस को कोसा। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने गंगा–यमुना के दोआब क्षेत्र में किसानों की अहमियत को समझते हुए सत्ता में आने पर गेहूं और गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा कर दी। कहा कि, भाजपा की सरकार आने पर गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि गेंहू का समर्थन मूल्य 1300 रुपए किया जाएगा। किसानों को खेती के लिए तीन फीसदी ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। एक वर्ष तक ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। बजट में कृषि पर दो से तीन फीसदी की राशि आवंटित करने पर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 14 फीसदी योगदान है। लगभग 55 से 60 फीसदी कामगार जुड़े हैं। कृषि की इस तरह से अनदेखी करने पर देश को विकास की पटरी पर नहीं लाया जा सकता। उन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के साथ–साथ सपा–बसपा को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराया।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कलराज मिश्र ने कहा कि मायावती के शासनकाल में अराजकता की स्थित पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर मायावती की संपत्ति जब्त कर उसे राज संपत्ति घोषित किया जाएगा। मौके पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही, प्रदेश प्रभारी श्री नरेंद्र तोमर, सह प्रभारी श्रीमती करुणा शुक्ला, श्री राधा मोहन सिंह, राष्ट्रीय सचिव श्री संतोष गंगवार एवं श्री किरीट सोमैया सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।■

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में सत्ता परिवर्तन की संभावना

l:tho d|ekj flUgk

ns श में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के निमित्त राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। असम, केरल, तमिलनाडू, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 27 अप्रैल, 3 मई, 7 मई और 10 मई को छह चरणों चुनाव कराए जाएंगे। असम में दो चरणों में 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को चुनाव कराया जाएगा। केरल, तमिलनाडू और पुडुचेरी में 13 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। मतों की गिनती 13 मई को होगी।

असम में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी के साथ भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं राजग के संयोजक श्री शरद यादव

इन चुनावों में केरल और पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों तथा असम, तमिलनाडू और पुडुचेरी में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। केन्द्र में हुए राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला और बेलगाम महंगाई के चलते कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के प्रति मतदाताओं में आक्रोश है। वहीं भाजपा असम में मजबूत स्थिति में है और सरकार गठन में पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसके साथ ही केरल और पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को पहले के मुकाबले अच्छी सफलता मिलने की संभावना है।

असम में कांग्रेस, भाजपा और असम गण परिषद् के बीच संघर्ष है। इस चुनाव में आतंकवाद, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, अवैध घुसपैठ और भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा है। भाजपा राज्य की सभी 126 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केरल में माकपानीत एलडीएफ एवं कांग्रेसनीत यूडीएफ तथा भाजपा के बीच मुकाबला होना है। यहां विकास, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, कानून एवं व्यवस्था, पेयजल की समस्या आदि मुद्दे है। इस बार भाजपा अपने गठबंधन सहयोगी जनता दल यू के लिए कुछ सीटों को छोड़कर सभी 140 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तमिलनाडू में द्रमुक, अन्नाद्रमुक, कांग्रेस और भाजपा प्रमुख राजनीतिक दल है। यहां द्रमुक और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। भाजपा ने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। विपक्षी दल 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा की संलिप्तता को मुद्दा बना रहे हैं। राज्य में द्रमुक और अन्नाद्रमुक पार्टी सहित निर्दलीय प्रत्याशी भी मतदाताओं को मुफ्त उपहार देने का वादा कर अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हैं। तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने पुनः सत्ता में आने पर छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया है तो इससे आगे बढ़कर विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने मुफ्त में पंखे, मिक्सी और छात्रों को लैपटॉप देने का वादा किया है वहीं कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने मतदाताओं को मुफ्त में नैनो कार देने की घोषणा की है। जबकि भाजपा ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो मुफ्त उपहार नहीं, बल्कि लोगों को ईमानदारी और पारदर्शी सरकार देगी। पुडुचेरी में द्रमुक, अन्नाद्रमुक, कांग्रेस और भाजपा प्रमुख राजनीतिक दल है। यहां भी भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में माकपा, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और भाजपा प्रमुख राजनीतिक दल है। यहां तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। इस चुनाव में नक्सली हिंसा, सरकारी आंतक, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है। भाजपा कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर प्रदेश की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

असम

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद का आह्वान करते हुए कहा कि इस समस्या ने केंद्र की संप्रग सरकार और कांग्रेस शासित असम को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। श्री आडवाणी ने कहा कि सरकार के प्रत्येक स्तर से भ्रष्टाचार

असम विधानसभा चुनाव के दौरान आयोजित संवाददाता सम्मेलन में लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज

को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लोगों को संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने 1 अप्रैल को राज्य के गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र के मेलमारा में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। श्री आडवाणी ने राज्य के सोनीतपुर जिले में रंगापारा विधानसभा क्षेत्र के बलीपारा में एक अन्य चुनाव रैली में दावा किया कि जिन राज्यों में राजग गठबंधन की सरकारें सत्ता में हैं, वहां हालात कांग्रेस शासित राज्यों से बहुत बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि असम में जनता स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए जूझ रही है। खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में इन मूलभूत सुविधाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने लोगों से मुख्यमंत्री तरूण गोगोई को यह संदेश देने को कहा कि राज्य में 10 साल तक शासन करने के बाद अब उन्हें आराम की जरूरत है। श्री आडवाणी ने कहा कि भाजपा ही उत्तरपूर्व राज्यों के हितों को पूरा करने में सक्षम है क्योंकि अन्य दलों ने स्थानीय जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है।

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने 29 मार्च को गुवाहाटी में कहा कि वह अपने दम पर सरकार बनाने के लिए असम विधानसभा चुनाव लड़ रही है और लोग कांग्रेस की राज्य और केंद्र सरकारों से निराश और दुखी हैं। श्रीमती स्वराज ने संवाददाताओं से कहा कि जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, आपका जोर सिर्फ जीतने पर होता है। इसी प्रकार हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य अपने दम पर सरकार बनाना है।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आरोप लगाया कि असम में अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों ने गड़बड़ी मचा दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और असम गण परिषद की सरकारों ने इस घुसपैठ को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। श्री मोदी ने लखीमपुर जिले के नाओबोइचा और पड़ोसी जिले धेमाजी में भाजपा की चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की सीमा पाकिस्तान से सटी है, जबकि असम की सीमा बांग्लादेश से सटी है। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में पाकिस्तानी कोई भी समस्या खड़ी नहीं कर पाए हैं। लेकिन असम में बांग्लादेशियों ने गड़बड़ी मचा दी है। श्री मोदी ने एलान किया कि भाजपा असम को कभी भी बांग्लादेश नियंत्रित राज्य नहीं बनने देगी।

केरल

भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं से वादा किया कि अगर वह सत्ता में आती है तो आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए विशेष विधेयक लाएगी। उल्लेखनीय है कि केरल में आगामी 13 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने सभी वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की और रोल मॉडल के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकास योजनाओं की रूपरेखा को पेश किया। घोषणापत्र में केन्द्र सरकार के वेतनमान के समानांतर राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन और गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण दने जैसी कई बातें कहीं गई हैं।

तमिलनाडू

राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों की तिथि को ध्यान में रखते हुए 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला मामले की जांच का समय निर्धारित करने का आरोप लगाया।

श्री जेटली ने 4 अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हजारों करोड़ रूपए के इस घोटाले में सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र का शुरूआती संकेत ही परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने चुनावों की तिथि के अनुरूप जांच की समयसारिणी निर्धारित की है ताकि सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को विधानसभा चुनावों में कोई दिक्कत न आए।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि चार राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा

चुनावों में सत्तारूढ़ सरकारें कुशासन और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के चलते हार जाएगी। श्री नायडू ने संवाददाताओं से कहा, 'भाजपा इन सभी राज्यों की विधानसभाओं में अपने दम पर प्रवेश करेगी और निश्चित तौर पर पहले से अच्छा प्रदर्शन करेगी।' उन्होंने कहा कि इन प्रदेशों में आजादी के 60 साल बाद भी बिजली, सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सात मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं।

श्री नायडू ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, 'पहले आप जनता को 24 घंटे बिजली प्रदान करें और तब उन्हें पंखे और मिक्सी बांटें। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक और उसकी चिर प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक दोनों ने ही अपने चुनावी घोषणापत्रों में जनता को मिक्सी, ग्रांइडर और लैपटॉप जैसे मुफ्त उपहार देने का वादा किया है।

तमिलनाडु में 13 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए द्रमुक और अन्नाद्रमुक की ओर से मुफ्त उपहारों की घोषणा की भाजपा ने कड़े शब्दों में आलोचना की है। पार्टी ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो मुफ्त उपहार नहीं, बल्कि लोगों को ईमानदारी और पारदर्शी सरकार देगी। पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण ने 26 मार्च को कहा द्रमुक और अन्नाद्रमुक सालों से प्रदेश का विकास करने में असफल रहे हैं और अब ये पार्टियां अपना सारा ध्यान मुफ्त उपहारों की घोषणा पर दे रही हैं।

द्रमुक और अन्नाद्रमुक की मुफ्त उपहार की घोषणाओं को छलावा मात्र करार देते हुए श्री लक्ष्मण ने कहा कि दोनों पार्टियां राज्य में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने में असफल रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह अपना सारा ध्यान राज्य के विकास पर लगाएगी। पार्टी घोषणापत्र का जिक्र करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पॉन राधाकृष्णन ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में 194 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मुफ्त उपहारों की झूठी घोषणा करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन वे इतना आश्वासन जरूर देंगे कि उनकी पार्टी ईमानदार और पारदर्शी सरकार देगी। घोषणापत्र के मुख्य मुद्दों का जिक्र करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक के साथ कावेरी जल विवाद का यथाशीघ्र निपटारा करेगी और राज्य के लिए सालाना 205 टीएमसी जल हासिल करने की कोशिश करेगीए जिससे कि डेल्टा क्षेत्र के किसानों की समस्या दूर हो सके।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल विधानस□ा चुनाव को लेकर प्रदेश □ाजपा ने 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करते हुए बेरोजगारी दूर करने, किसानों की दशा व कानून व्यवस्था सुधारने, उद्योग के लिए माहौल बनाने, जमीन देने वालों को नौकरी देने, अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास तथा गोरखालैंड के राजनीतिक समाधान का संकल्प जताया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार ने कोलकाता स्थित प्रेस क्लब में घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर प्रदेश □ाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा, श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री तथागत राय व शमिक □ट्टाचार्य मौजूद थे।

घोषणा पत्र में विधान परिषद के पुनर्गठन के प्रयास, हर नागरिक को राजनीतिक स्वतंत्रता देने, लैंड बैंक तैयार करने, छोटे उद्योग को बढ़ावा देने, कृषि प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाने, किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने, उत्तर बंगाल के विकास और कोयला माफियाओं के राज खत्म करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में लाडली लक्ष्मी योजना राज्य में लागू करने की बात कही गई है। उद्योग धंधे की लचर हालत होने का आरोप लगाते हुए श्री अनंत कुमार ने राज्य की उद्योग नीति में परिवर्तन की जरूरत बताई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य की कुछ राजनीतिक पार्टियों के सहारे बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ जारी है। पार्टी सीमा पर उचित व्यवस्था के लिए केन्द्र पर दबाव डालेगी। ■

घुसपैठियों से मुक्त उन्नत असम हमारा सपना : गडकरी

Hkkजपा प्रमुख श्री गडकरी ने कहा कि असम बेहतर शासन का हकदार है और भाजपा यही सुशासन असम को प्रदान करने का वायदा करती है और असम को एक उन्नत राज्य बना कर इसे घुसपैठियों से मुक्त करना चाहते हैं। वे गुवाहाटी में 'विजन डाक्युमेंट (दृष्टि–पत्र)' को जारी कर रहे थे– ''हमारे स्वप्नों का असमः असम विजन 2025''। भाजपा अध्यक्ष ने विजन डाक्युमेंट के विमोचन के लिए आयोजित समारोह में बोलते हुए कहा कि ''भाजपा का सुशासन प्रदान करने का निरन्तर एक रिकार्ड रहा है और आज देश में भाजपा अथवा एनडीए शासित सभी प्रदेशों में विकास के सभी प्रकार के पैरामीटरों पर प्रगति दिखाई पड़ती है। भाजपा द्वारा शासित अनेक राज्यों में तथा गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश ने बेहतर प्रकार के शासन प्रदान करने के लिए कई एवार्ड भी प्राप्त किए हैं। श्री गडकरी मुम्बई–पुणे एक्सप्रेस वे का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए तथा विश्वस्तर के सड़क नेटवर्क और कम–लागत पर प्रमुख रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हेलीकाप्टर कनेक्टिविटी के निर्माण कार्य के लिए विख्यात रहे हैं। श्री गडकरी ने यह कहते हुए कांग्रेसी सरकारों की आलोचना भी की कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटित संग्रहीत धनराशि राजनीतिज्ञों की जेब में पहुंच जाती है तथा असम के लोग विकास के मामले में निरंतर ज्यों की त्यों स्थिति में बने रहते हैं। श्री गडकरी ने यह बात भी जोर देकर कही कि ''हम देखते हैं कि असम के सभी प्रकार के विकास सूचकांक भ्रष्टाचार के कारण वैसे ही बने हुए हैं और उधर गोगोई सरकार का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है।'' श्री गडकरी ने यह भी कहा कि 'विजन डाक्युमेंट' में अनेक प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहन दिए गए हैं, जैसे जो उद्योगपति राज्य में अपनी विनिर्माण ईकाई स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें 'टैक्स होलीडे' का लाभ मिलेगा।

विजन डाक्युमेंट में कुछ ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन सम्बन्धी वायदे भी किए गए हैं जिन्हें भाजपा सरकारों ने सफलतापूर्वक चलाया है। पशुपालन, पेट्रोलियम विज्ञान जैसी विधाओं के प्रति समर्पित स्वतंत्र विश्वविद्यालयों तथा 'राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट' (अर्थात् चावल अनुसंधान संस्थान) की स्थापना के अलावा विजन डाक्युमेंट में ऐसी कुछ अन्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने की बात रही गई है। जिन्हें भाजपा सरकार ने सफलतापूर्वक चलाया है। इनमें से प्रमुख है– गुजरात में मृदा–स्वास्थ कार्ड योजना, कर्नाटक की ई–प्रोक्योरमेंट मॉडल, छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना और हिमाचल प्रदेश की पर्यावरण –अनुकूल नीतियां। अन्य बातों के अलावा इस विजन डाक्युमेंट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, नगर विकास केन्द्रों के रूप में शहरों का विकास आगे

'विजन डाक्यूमेन्ट' का विमोचन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती विजया चक्रवर्ती, राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल।

बढ़ने वाले उद्यमियों के लिए उद्योग विश्वविद्यालयों के साथ गठजोड़ कर विचार केन्द्र स्थापना, ब्रह्मपुत्र पर पर्याप्त रेल–सड़क पुलों का निर्माण, डिलीवरी मैकेनिज्म बढ़ाने के लिए प्रमुखतः ई–गवर्नेंस सिस्टम और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जीपीएस, जीआईएस जैसी बायो–मैट्रिक्स आदि नवीनतम टेक्नालाजियों को शुरू करना। विजन डाक्युमेंट में गुवाहाटी जैसे महानगरों में मैट्रो और मोनो–रेल, माल परिवहन के लिए कोंकण रेलवे टाइप की दो–दो सिस्टम शुरू करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा, हथकरघा के लिए एक आदर्श सहकारी टाउनशिप के रूप में सुलकुची के विकास के अलावा इसमें मुगा और अन्य स्थानीय हथकरघाओं के लिए एक अनुसंधान और विकास संस्थान की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। 75 पृष्ठ के डाक्युमेंट में 35 अध्याय हैं। इसमें राज्य के चाय बागान के आदिवासी एवं अन्य आदिवासी समुदायों की विशेष योजनाओं तथा बराक घाटी के विकास के लिए स्वतंत्र बराक बोर्ड की स्थापना की बात भी कही गई है।

इस अवसर पर असम भाजपा नेतागण तथा गुवाहाटी के आसपास से आए पार्टी के उम्मीदवार भी उपस्थित थे। बुद्धिजीवियों तथा नीति विशेषज्ञों के गहन विचारविमर्श से तैयार किए गए। इस डाक्युमेंट को वेबसाइट ww.bjpasomvision2025.org पर भी प्रकाशित किया गया है। अन्य लोगों के अलावा श्री देवधर के नेतृत्व में भाजपा के पूर्वोत्तर सम्पर्क प्रकोष्ठ इस डाक्युमेंट की मानीटरिंग कर रहा है। इस अवसर पर तीन पुरूस्कारों के विजेता प्रफुल्ल कुमार कलीता, बोंगाई गांव, स्वप्निल बरूआ, उदालगिरी और नगेन्द्रनाथ सर्माह, गुवाहाटी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गुवाहाटी के एक युवा प्रोफेशनल विक्रम राजखोआ ने 'पावर प्वाइंट प्रेजेण्टेशन की प्रस्तुति की। ■

चुनावों में कालाधन का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस

भाजपा उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा 27 मार्च को नई दिल्ली में जारी वक्तव्य

Hkkजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आगामी पांच विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दल बड़ी तादाद में ''करप्शन करन्सी को कैम्पेन करन्सी,'' के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल एवं पाण्डिचेरी में भ्रष्टाचार के काले धन के रथ पर सवार होकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, पिछले दिनों दिल्ली हवाई अड्डे पर कांग्रेस के एक सहयोगी दल के सांसद का लाखों रुपया लेकर जाते पकड़ा जाना, और फिर बिना कार्यवाही के छोड़ दिया जाना ''काले धन'' के इस्तेमाल एवं कांग्रेस का काले धन को संरक्षण का एक छोटा सा उदाहरण है।

श्री नकवी ने कहा, जो भाजपा के चुनाव प्रबन्धन एवं समन्वय के प्रभारी भी हैं, कि इन पांचों राज्यों में कांग्रेस एवं उनके सहयोगियों का ''भ्रष्टाचार एवं लूट'' साझा कार्यक्रम का हिस्सा होता है और इसी ऐजेन्डे को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार से इकठ्ठा काले धन को पानी की तरह बहाया जाता है ।

असम, पश्चिम बंगाल आदि के चुनावी दौरे से लौटने के बाद श्री नकवी ने कहा कि चुनाव आयोग को कांग्रेस द्वारा पानी की तरह बहाये जा रहे काले धन की रोकथाम एवं अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री नकवी ने कहा कि पानी की तरह बहाया जा रहा यह कालाधन भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के डूबते जहाज को नहीं बचा सकता, क्योंकि केन्द्र सरकार के कारनामों के चलते देश में फैली अव्यवस्था, अराजकता, असंतोष चरम पर है, और उसके लिए कांग्रेस और उसके नेतृत्व में चल रही सरकार जिम्मेदार है ।

श्री नकवी ने कहा कि इन सभी पांचों चुनावी राज्यों में अधिकांश सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, भ्रष्टाचार, घुसपैठ, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद, कुशासन, काला धन प्रमुख मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर ''भाजपा सशक्त विकल्प, सुशासन के संकल्प'' के साथ चु नाव अभियान चला रही है ।

श्री नकवी ने असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, की कुल 824 विधनसभा सीटों पर भाजपा ने 800 से ज्यादा सभाओं, रैलियों आदि के कार्यक्रम रखे हैं जिसमें भाजपा के प्रमुख नेता, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री नितिन गडकरी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली, डा0 मुरली मनोहर जोशी, श्री एम. वैंकेया नायडू, श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेन्द्र मोदी, सहित सभी प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री, भाग लेंगे। ■

कांग्रेस देश की सभी समस्याओं की जड़ : नितिन गडकरी

&gekjs laoknnkrk }kjk

Hkkजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद झारखंड के प्रथम दो दिवसीय दौरे पर आए नितिन गड़करी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में व्याप्त सभी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी देश के लिए धीरे–धीरे कैंसर बन गई है। यदि देश को महंगाई और भुखमरी और आतंकवाद से मुक्त कराना है तो उसे पहले कांग्रेस के कुशासन से मुक्त कराना होगा। जनविरोधी नीतियों के कारण देश में महंगाई, भ्रष्टाचार बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। कॉमन वेल्थ गेम व 2जी स्पक्ट्रम घोटाले की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार में कई रिकार्ड कायम किए हैं।प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार के हर मसले पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं। वह यह भी कहते हैं कि आप जितना समझ रहें हैं, मैं उतना दोषी नहीं हूं। हम उनसे इतना पूछना चाहते हैं कि उतने नहीं तो कितने दोषी हैं आप, यह तो बताएं। भाजपा उपरोक्त तीनों समस्याओं को लेकर 6 अप्रैल से 20 दिनों तक आंदोलन करेगी। श्री गड़करी ने भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह पार्टी किसी मां–बेटे की पार्टी नहीं है।देश के संविधान में भाजपा की पूर्ण आस्था है।श्री गड़करी ने कहा कि देश के नौ राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है, जिनमें से सात में उनके मुख्यमंत्री है और दो में उपमुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोग राष्ट्र को प्रथम ,पार्टी को द्वितीय और स्वंय को तीसरे स्थान पर रखते हैं। उन्होंने कहा कि वे आज महात्मा गांधी ,दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ–साथ झारखण्ड के शहीद बिरसा मुडा, तिलका मांझी ,सिद्धू कान्हू और नीलांबर पीतांबर के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर अपने को गौरवांवित महसूस करते है। भाजपा कार्यकर्ताओं को सत्ता परिवर्तन के माध्यम से समाज में परिवर्तन का मंत्र देते हुए उन्होंने एलान किया कि 2014 में केन्द्र में एनडीए की सरकार बनेगी। आज देश में व्याप्त जन–विद्रोह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अर्जुन मुंडा सरकार की सराहना की और कहा कि अगले छह माह से एक साल तक में विकास का काम दिखने लगेगा इस सरकार को बनाने के निर्णय में मैं भी शामिल था। अर्जुन मुंडा अच्छा कार्य कर रहे हैं। श्री गडकरी ने संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट शब्दों कहा कि जमशेदपुर सीट भाजपा की है। यह सीट दूसरे की हो ही

झलकियां

- *मंच पर स्थान लेने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा नेताओं और देश के शहीदों को नमन किया।*
- *प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता पढ़ी, तो यदुनाथ पांडेय ने देष भक्ति गीत सुनाये।*
- *मंच के आसपास गड़करी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवानी, अर्जुन मुंडा दिनेशानंद गोस्वामी के कट–आउट लगाये गये थे।*

नही सकती

श्री गडकरी ने कहा कि पार्टी नेताओं को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अगली बार भाजपा में खुद की सरकार हो। संगठन की मजबूती पर ध्यान देने की बात को दोहराते हुए श्री गडकरी ने कहा कि हमें कार्यकर्ता के निर्माण पर ध्यान देना होगा और अपने बूते सरकार बनाने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र में भाजपा के लिए अनुकूल माहौल है और सांसदों की यहां संख्या बढ़ायी जा सकती है।

इस अवसर पर अर्जुन मुंडा ने केन्द्र सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि केन्द्र सरकार ने झारखण्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया है। राज्य को सूखा में केन्द्र सरकार से जो सहयोग मिलना, वो नहीं मिला। झारखण्ड की कोयला, स्वर्णरेखा मयूराक्षी नदी के पानी का हिस्सा दूसरे राज्यों को जाता है, हमारे हिस्से में कम पानी मिला है, हम नहीं चाहते कि दूसरे राज्यों को पानी नहीं मिले, लेकिन हम प्यासे रहें ,नहीं चलेगा। श्री मुंडा ने आगे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कर्णपुरा थर्मल पावर का शिलान्यास किया था, अब कोयला मंत्रालय इस पर अपनी सहमति नहीं दे रहा है। यह झारखण्ड की जनता के साथ विश्वासघात है। ■

केन्द्र सरकार झुकी
अन्ना हजारे का अनशन खत्म

भ्रष्टाचार रोकने को लेकर जन लोकपाल विधेयक लाने की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 5 अप्रैल से नई दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठे। हजारे को अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी समर्थन मिलने के बाद केन्द्र सरकार को झुकना पड़ा। अनशन प्रारंभ होने के चार दिन बाद 9 अप्रैल को अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की प्रति मिलने के बाद अपना अनशन समाप्त किया।

72 वर्षीय हजारे ने नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें उनके साथ स्वामी अग्निवेश, पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी और मैग्सायसाय पुरस्कार विजेता संदीप पांडे सहित अनेक जानेमाने लोग उपस्थित थे। इससे पहले उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हजारे ने राजघाट में कहा, ''मैं तब तक आमरण अनशन पर रहूंगा जब तक सरकार जन लोकपाल विधेयक का मसौदा बनाने वाली संयुक्त समिति में 50 प्रतिशत अधिकारियों के साथ शेष में नागरिकों और विद्वानों को शामिल नहीं करती।'' इसके बाद वह एक खुली जीप में इंडिया गेट की ओर रवाना हुए जिस दौरान स्कूली बच्चे और तिरंगा लहराते समर्थक उनके साथ थे। हजारे ने प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद अपना अनशन शुरू किया।

जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर आमरण अनशन पर बैठे अन्ना हजारे और उनके दर्जनों सहयोगियों ने 9 अप्रैल को केंद्र सरकार के साथ समझौता हो जाने के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। अन्ना हजारे ने एक बच्ची के हाथ से नींबू का रस लेकर अनशन तोड़ा। अपने बाकी साथियों का अनशन उन्होंने खुद अपने हाथों से तुड़वाया। इससे पहले वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि जनता की शक्ति की वजह से ही लोगों को यह जीत हासिल हुई है। श्री हजारे ने केंद्र सरकार को जन लोकपाल बिल को संसद में पास करवाने के लिए 15 अगस्त तक की मोहलत दी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि यह तो उसकी शुरूआत भर है।

जन लोकपाल विधेयक के मुद्दे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार इस ''ऐतिहासिक विधेयक'' को संसद के मानसून सत्र में पेश करना चाहती है। केन्द्र सरकार ने लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से दस सदस्यीय संयुक्त समिति बनाने के लिए एक औपचारिक आदेश जारी किया। समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी होंगे। इसमें कानून मंत्री वीरप्पा मोइली दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल गृहमंत्री पी. चिदंबरम और जल संसाधन मंत्री सलमान खुर्शीद सदस्य के रूप में शामिल होंगे। गैर सरकारी पक्ष की ओर से हजारे के अतिरिक्त जाने माने अधिवक्ता शांति भूषण प्रशांत भूषण उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संतोष हेगड़े और आरटीआई कार्यकर्ता अरविन्द केजरीवाल इस संयुक्त समिति में शामिल होंगे। शांति भूषण समिति के सह अध्यक्ष होंगे।

लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार से मुक्त भारत चाहती है और सख्त लोकपाल विधेयक तैयार होने की स्थिति में वह संसद में उसका समर्थन करेगी। श्री गडकरी ने सीआईआई के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि हम लोकपाल विधेयक का समर्थन करेंगे। ■

गरीब, पिछड़े एवं शोषित को भगवान मान निरंतर सेवा करना हमारा संकल्प : गड़करी

loknnkrk }kjk

Hkkजपा के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन मावलंकर हॉल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गड़करी, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) रामलाल जी, उपस्थित थे। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार मल्होत्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावेड़कर, दिल्ली की राष्ट्रीय मंत्री सुश्री आरती मेहरा, एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विंजेन्द्र गुप्ता आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

सभागार में उपस्थित सभी लोगों व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि हमने आज 31 साल पूरे किए हैं लेकिन जनसंघ के समय से देखें तो हमने 60 साल पूरे किए हैं। उन्होंने एक पंक्ति भी कही कि ''कभी प्रकाश या अंधकार या कभी विजय या हार था।''

उन्होंने आगे कहा कि कोई हमें पसंद करे या न करे। इसकी परवाह किए बिना हमें आगे बढ़ना होगा। आज हमारे पास 8 राज्यों की सरकारें हैं। और मैं निश्चित ही कहूंगा कि आगे आगामी 5 राज्यों के चुनावों में से एक राज्य में हमारी सरकार होगी।

साथ ही उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रगति कर रहे हैं।ये प्रगति हमारे लिए प्रेरणा है। मंत्री पद त्यागकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए जो कार्य किया जो काफी महत्वपूर्ण था। अगर सरकार ने श्यामा प्रसाद जी के कश्मीर समस्या को लेकर डा0 मुखर्जी की बात सुनी होती तो आज यह समस्या उत्पन्न नहीं होती।

भाजपा का मुख्य उद्देश्य है देश की सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करना, जातिवाद आदि को जड़ से खत्म करना।

श्री गड़करी ने कहा कि कार्य बड़ा होता है न कि जाति। साथ ही उन्होंने पं0 दीनदयाल उपाध्याय के विचार को उद्धृत करते हुए कहा कि जो गरीब, पिछड़े हैं शोषित हैं उन्हें भगवान मानकर व उनकी निरंतर सेवा करनी होगी। श्री गडकरी ने आगे कहा कि हम आधुनिकीकरण के पक्षधर हैं और आगे चलकर विज्ञान के सहारे हम 21 वीं सदी का भारत बना सकते हैं। जो अच्छा विचार है हम उसे यूरोपीय मॉडल से स्वीकार करेंगे।

केशवानंद भारती केस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल रूप में बदलाव पर आपत्ति जताई थी, ठीक उसी प्रकार हम अपने मूल लक्ष्य पर अडिग हैं। और हमारी पार्टी के पक्ष में गलतफहमी फैलाई जाती है कि ये पार्टी पूंजीपतिवर्ग की है। भारतीय जनता के मन में नकारात्मक सोच पार्टी के विरूद्व पैदा की जा रही है। यह स्थिति इमेज़ और रियल्टी वाली है। मैं आप लोगों से एकबात कह दूं कि यह पार्टी किसी एक की पार्टी नहीं है, बल्कि सामूहिक विचारों की पार्टी जो किसी एक के कहने पर नहीं चलती बल्कि सामूहिक विचार एवं सभी के समर्थन से ये पार्टी चलती है।

उन्होंने कहा कि सरकार 'एक्स (पूर्व)' हो सकती है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता कभी 'एक्स(पूर्व)' नहीं हो सकते। भाजपा का लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापना। आज देश में 50 प्रतिशत व्यक्ति की प्रतिव्यक्ति आय 20 रूपये कम है। 10 लाख

किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। नक्सलवाद के कारण देश आज हिंसा को झेल रहा है। भारत–चीन सीमा विवाद चिंता का विषय है। आतंकवाद देश के लिए खतरा बन रहा है । आज आतंकवाद का तुष्टिकरण हो रहा है। सरकार आतंकवाद के पक्ष में वोट बैंक बटोर रही है। देश के सामने सबसे बड़ी तीन समस्याएं हैं भ्रष्टाचार , काला धन ,और महंगाई। जिनसे निपटने के लिए भाजपा ने रणनीति बनाई हुई है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हम विज्ञान अर्थात् आई टी का सहारा लेंगे ताकि विदेशों में ई–बैंकिग हो। टेंडर ग्लोबल हो जाएगा। भ्रष्टाचार एक कैंसर है । वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार ने सभी रिकोर्ड़ तोड़ दिए हैं। हम ऐसी आर्थिक नीति अपनाएंगे जिससे भ्रष्टाचार जड़ से ही खत्म हो जाएगा। भारत 'विज़न –2025' का स्वप्न पूरा होगा

श्री गडकरी ने कहा कि हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं है।भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो ऐसा हमारा स्वप्न एवं लक्ष्य है। बिहार और मध्य प्रदेश जहां हमारी सरकारें हैं वहां पर भ्रष्टाचार विरोधी नेता को न्यायालय में पेश किया जाएगा और यदि न्यायालय द्वारा उन पर लगाया गया आरोप सत्य पाया जाएगा तो उस नेता की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

काले धन पर बोलते हुए श्री गडकरी ने कहा कि काला धन एक संवेदनशील विषय है। हम देश में काला धन वापिस लाएंगे और उसे गरीबों में वितरित करेंगे क्योंकि वो पैसा गरीबों का है। उनकी खून और पसीने की कमाई है। हम आज के समाज को ध्यान में रखते हुए सुशासन के साथ–साथ सामाजिक –आर्थिक विकास प्राप्त करेंगे। हम सब एक हैं और समाज के लिए कार्य करेंगे आने वाले समय में हम एकजुट हों।

उन्होंने आगे कहा कि 2014 का लोकसभा चुनाव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार रूप देना होगा जिसमें उन्होंने एक सुखी, समृद्ध भारत की तस्वीर हमारे सामने रखने की कोशिश की थी। हम निश्चित तौर पर एक ऐसे भारत का निर्माण अवश्य करेंगें जो सुखी और समृद्ध होगा। समारोह का शुभारंभ श्री गडकरी के द्वारा दीप प्रज्जवलित और वंदे मातरम् राष्ट्र गीत से हुआ। इसके बाद उन लोगों का सम्मान किया गया जो 1948 के समय में जेलों में बंद थे। इनमें शामिल थे श्रीमती शकुंतला आर्य, सर्वश्री श्रद्धानंद जी, रामचंद्र नेगी, उमराव सिंह पिन्डोलिया, इन्द्रा पसीजा आदि। चौधरी लज्जा राम केदारनाथ सचदेवा जो 19 वर्षों से जेल में कैद थे। चौधरी लज्जा राम का स्वागत करने के लिए श्री गडकरी स्वयं मंच से नीचे उतरे क्योंकि श्री लज्जा मंच पर चढने में अक्षम थे।

इस समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल जी ने कहा कि हमें बुजर्गों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये पार्टी किसी एक की नहीं,न किसी परिवार की, न ही किसी पूंजीपति की। यह पार्टी किसी एक प्रदेश की नहीं, न ही पंथ की है। ये विचारधारा की है। पार्टी को केवल अपने चर्चा से नहीं कार्यकर्ताओं ने अपने खून और पसीने से सींचा है। कार्यकर्ताओं ने कई बलिदान दिए है। श्री रामलाल ने पार्टी के भौगोलिक और सामाजिक विस्तार बनाने पर बल दिया। पुरानी पीढ़ी ने भाजपा को शीर्ष पर लाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है और अब नई पीढी को भाजपा को शीर्ष पर ले जाने के लिए और जनभागीदारी बढाने के लिए कार्य करना चाहिए।

दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा ने भी भाजपा के इतिहास एवं विकास पर प्रकाश नज़र डालते हुए भाजपा को लोककल्याणकारी और सर्वहित संपन्न पार्टी की संज्ञा दी। ■

हिमाचल जब्त करेगा काली कमाई : धूमल

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने का निर्णय किया है। इससे संबंधित बिल आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून में भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए कई प्रावधान किए जाएंगे। राजधानी में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कानून से जुड़े लोगों का आह्वान किया कि जनता को शीघ्र न्याय मुहैया करावाया जाए। उन्होंने कहा कि देरी से न्याय की महत्ता कम हो जाती है और ऐसा न्याय प्रभावित व्यक्तियों के लिए अहितकारी सिद्ध होता है। उन्होंने जांच एजेंसी की ओर से मामलों के शीघ्र जांच की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे न्यायलयों द्वारा इन मामलों को शीघ्र ही निपटारा सुनिश्चित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधिक एंव संवैधानिक पहलुओं पर भी नई सोच की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को जारी रखने का भी निर्णय लिया है। बैठक में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति पर्वत राव, राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष बलदेवराज महाजन, उपाध्यक्ष एमपी बेंद्रे, राष्ट्रीय संगठन सचिव कमलेशसिंह, पूर्व अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डी भरत कुमार के अलावा देश के विभिन्न भागों से आए परिषद के सदस्य उपस्थित हुए। ■

भ्रष्टाचार, महंगाई, घोटालों एवं कालेधन के विरुद्ध
भाजपा का राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष 6 अप्रैल से

Hkkरतीय जनता पार्टी 06 अप्रैल से भ्रष्टाचार, मंहगाई, घोटालों एवं विदेशों में जमा कालेधन के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी ''जनसंघर्ष '' शुरू करेगी।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय कार्यक्रम एवं अभियान प्रभारी श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 06 अप्रैल से शुरू हो रहे ''जनसंघर्ष'' के तहत पार्टी देश के सभी जिलों में जनसंघर्ष रैलियों एवं भ्रष्टाचार विरोधी मैराथन के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ प्रभावी एवं आक्रामक अभियान चलाएगी। जनसंघर्ष अभियान का पहला चरण 15 जून तक चलेगा। यह कार्यक्रम पांच चुनावी राज्यों में चुनाव के बाद होंगे।

श्री नकवी ने बताया कि जिलों में जनसंघर्ष रैलियों से पूर्व जन जागरण पद यात्राएं एवं प्रभात फेरियों का कार्यक्रम होगा। जिसके माध्यम से जन जन तक भ्रष्टाचार, घोटालों एवं मंहगाई के विरूद्ध जनसंघर्ष में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति की भागीदारी की अपील की जायेगी।

श्री नकवी ने बताया कि नगरों, महानगरों एवं नगर पंचायतों में ''भ्रष्टाचार विरोधी मैराथन'' का आयोजन किया जायेगा जिसमें नौजवान, महिलाएं एवं आम लोग जनसंघर्ष अभियान के संदेश को चौक, चौराहों, गली, मोहल्लों तक पहुंचाने हेतु साईकिल, मोटर साईकिल एवं पैदल, भ्रष्टाचार विरोधी मैराथन में भाग लेंगे। जनसंघर्ष अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मेरठ में विशाल रैली होगी जिसमें श्री नितिन गड़करी, श्री राजनाथ सिंह, श्री कलराज मिश्र एवं अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे, इसके अतिरिक्त 18 अप्रैल को वाराणसी, 27 अप्रैल को आगरा एवं 26 अप्रैल को अयोध्या में भी रैलियां होंगी।

श्री नकवी ने बताया कि जन संघर्ष अभियान के तहत देश के विभिन्न भागों में आम आदमी पर है भारी–सिंहासन यह भ्रष्टाचारी नामक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से काले धन, मंहगाई एवं घोटालों के विरूद्ध जन जागरण किया जायेगा। युवाओं की कई टोलियां देश के सभी राज्यों में स्थानीय भाषाओं में आम आदमी पर है भारी–सिंहासन यह भ्रष्टाचारी नुक्कड नाटक का मंचन करेगी।

श्री नकवी ने बताया कि 'जन संघर्ष' अभियान के तहत संगीत एवं गीत के माध्यम से भी भ्रष्टाचार, कालेधन, मंहगाई, की परत दर परत उखेड़ी जायेगी और गीतों के माध्यम से भ्रष्टाचार एवं घोटालों के सच एवं कांग्रेस नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के भ्रष्टाचार एवं घोटालों में शामिल होने के हर पहलू को लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जायेगा। इस उद्देश्य से ''भ्रष्टाचार गीत माला'' की एक सीड़ी भी आज रिलीज की जा रही है।

श्री नकवी ने कहा कि 06 अप्रैल को जन संघर्ष अभियान के तहत दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी शामिल रहेंगे। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 6 अप्रैल से ''जनसंघर्ष'' का प्रभावी कार्यक्रम होगा। 06 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है एवं लोक नायक जय प्रकाश नारायण द्वारा छेड़े गये ''भ्रष्टाचार के विरूद्ध'' आन्दोलन का प्रमुख दिन भी है। ■

लोकपाल बिल प्रभावी बने

भाजपा के संसद सदस्य, महासचिव एवं मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा अप्रैल 05, 2010 को जारी प्रेस वक्तव्य

आज पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा करता है। भाजपा का यह मत है कि देश की इच्छा का सम्मान होना चाहिए और यह हम सभी का संवैधानिक दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि लोकपाल बिल प्रभावी और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रामाणिक कार्यवाही का माध्यम बनना चाहिए और इसके दायरे में राजनैतिक नेता और नौकरशाह दोनों आने चाहिए। साथ ही इस दिशा में जल्दी अपेक्षित कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अन्ना हजारे एक वरिष्ठ गांधीवादी नेता है और हम उसका सम्मान करते हुए उनसे आग्रह करेंगे कि वे अपना अनशन वापिस लें। जन–लोकपाल बिल के सन्दर्भ में सरकार को आन्दोलन–कारियों से चर्चा करनी चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस दिशा में पहल करनी चाहिए। ■

भारत की गिरती साख

&cychj i¦t

Dया संप्रग–2 के पापों से सरकार और कांग्रेस की ही हानि हुई है? इस पाप का हिसाब तो जनता उचित समय पर ले लेगी, किंतु वास्तविक हानि तो भारत की हुई है, जो अपूरणीय है। पिछले दिनों मैं लंदन प्रवास पर था। वहां के बुद्धिजीवियों से हुई बातचीत और भारत के संदर्भ में स्थानीय समाचारपत्रों में जो खबरें पढ़ीं, उनसे भारत की नकारात्मक छवि बनने का ही संकेत मिलता है। कुछ पाश्चात्य समीक्षक तो भारत का हश्र रूस की तरह होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जहा आर्थिक विकास के लिए नागरिकों को अपनी व्यावसायिक बुद्धि, कार्यदक्षता और परिश्रम के सहारे न रहकर भाईभतीजावाद पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था और अपराधियों पर आश्रित रहना पड़ता है।

लंदन से प्रकाशित 'फाइनेंसियल टाइम्स' के 22 मार्च के सस्करण में भारत से सबधित एक समीक्षा छपी थी, जिसका शीर्षक था–'राइटिंग इज ऑन द वाल।' नीचे राष्ट्रमडल खेलों के लोगों के साथ दीवार पर लिखा था, 'स्पोर्ट्स , गवर्नमेंट (फेल)।' खबर में आगे भ्रष्टाचार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंच रही क्षति और उसके कारण भारत की गिरती वैश्विक छवि की विस्तृत समीक्षा छपी थी। साथ ही ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के उक्त पत्र का भी हवाला था, जो उन्होंने फरवरी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था। पिछले साल भारत दौरे पर आए कैमरन ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक सपर्को को नया आयाम देने की बात की थी, किंतु ब्रितानी निवेशकों को यहा जिस तरह की लालफीताशाही झेलनी पड़ रही है उससे एक साल में ही उनका मोहभंग हो गया है। कैमरन ने आर्थिक सुधारों के पितामह मनमोहन सिह से दो–टूक पूछा, 'क्या नौकरशाहों और कुछेक शक्तिसपन्न व्यापारिक घरानों द्वारा अर्थव्यवस्था का गला घोंट डालने वाला 'लाइसेंसी राज' आज भी कायम है?' कैमरन अकेले नहीं हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मुंबई स्थित मुख्य अर्थशास्त्री समिरन चक्रवर्ती ने अपने हाल के अमेरिकी दौरे के दौरान निवेशकों में भारत के प्रति निराशा देखी। उपरोक्त आर्थिक समीक्षा में जमशेद गोदरेज, केशव महिंद्रा, बैंकर दीपक पारिख, अजीम प्रेमजी जैसे उद्योगपतियों द्वारा भारत में व्याप्त लालफीताशाही और भ्रष्ट नौकरशाही पर गहरी चिंता व्यक्त किए जाने का उल्लेख है। इन उद्योगपतियों ने अपने एक खुले पत्र में लिखा था, 'सरकार, व्यापार, सस्थागत कार्यो आदि राष्ट्रीय जीवन के प्रायः हर क्षेत्र से गायब होते सुशासन से हम गहरे चितित हैं।'

कैमरन की आशंका निराधार नहीं है। राडिया फोन टेप प्रकरण से वर्तमान सत्ता अधिष्ठान में कुछेक व्यापारिक घरानों की गहरी दखलंदाजी का ही खुलासा हुआ था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की लारा अल्फारो और नार्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय की अनुशा चारी ने आर्थिक सुधारों के प्रभावों का अध्ययन किया है। उन्होंने लिखा है, 'उदारीकरण के दौर से पूर्व जो कंपनिया बाजार में उपस्थित थीं उन्होंने बदली अर्थव्यवस्था में भी नए प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा लाभ अर्जित करना जारी रखा।' प्रसिद्ध समीक्षक ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि आर्थिक सुधारों से उदारीकरण की स्वाभाविक अपेक्षा थी, किंतु इससे वास्तव में भ्रष्ट राजनेताओं के ही वारेन्यारे हुए।

रूस में सन् 2000 में करोड़पतियों की सख्या एक हजार थी, जो 2010 मे बढ़कर 21,000 हो गई। वहीं भारत में सन् 2000 में जहा 4000 करोड़पति थे, वहीं 2010 में करोड़पतियों की सख्या 26,000 हो गई। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एक अरब बीस करोड़ की आबादी वाले इस देश में 69 अरबपति हैं। उनकी संपत्ति देश के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 30 प्रतिशत से भी अधिक है। सन् 2009 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश के पचास अरबपतियों के पास जीडीपी के 20 प्रतिशत से भी अधिक की सपत्ति और स्टॉक मार्केट की 80 फीसदी पूंजी है। संसाधनों और सत्ता के अत्यधिक नियंत्रण के कारण विकास और सुधार, दोनों पर स्वाभाविक रूप से प्रतिकूल असर पड़ता है। संप्रग–2 के पतन का कारण सप्रग सरकार की पहली पारी में कम्युनिस्टों के समर्थन वापस ले लिए जाने के बाद सत्तासुख भोग के लिए की गई सौदेबाजी है। अल्पमत में आ गई सरकार को सदन में विश्वासमत हासिल करना था। संप्रग सरकार ने नोट के बदले वोट खरीद कर सदन में बहुमत साबित कर दिया। अब विकिलीक्स ने यह खुलासा किया है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने सांसदों को घूस देकर विश्वासमत हासिल किया था। इस खुलासे के बाद सदन में प्रधानमंत्री ने अपनी सफाई में कहा है कि वोट की खरीद–फरोख्त नहीं हुई, जबकि नोट के बदले वोट की जाच के लिए गठित किशोरचंद देव समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि

सांसदों को रिश्वत दी गई थी। रिश्वत के लिए करोड़ों रुपयों की धनराशि कहां से आई? इसमें किन व्यापारिक घरानों का हाथ था? इस उपकार के लिए संप्रग–2 ने सरकार बचाने वाले व्यापारिक घरानों के व्यावसायिक हितों को न केवल पहली प्राथमिकता दी, बल्कि नीति–निर्धारण में उन कंपनियों की अनुचित दखलंदाजी को भी चुपचाप सहा।

राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में हुई अनियमितता की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित शुंगलू समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। खेल गांव के अंदर हजार लैफ्टों के निर्माण में निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए शुंगलू समिति ने दिल्ली के राज्यपाल को दोषी ठहराया है, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी घोटालों का जिम्मेदार भी ठहराया है, किंतु वास्तविकता यह है कि केंद्रीय सत्ता शिखर भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में खड़ा है। शुंगलू समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई न कर प्रधानमत्री संबधित विभागों से उनकी टिप्पणी मांग रहे हैं। ऐसे में समिति गठित करने का क्या लाभ? क्या यह महज लीपापोती करने का प्रयास नहीं है? आइपीएल, राष्ट्रमंडल खेल, 2जी स्पेक्ट्रम, सेटेलाइट स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी घोटाला, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर दागदार व्यक्ति की नियुक्ति और इन सब घोटालों से प्रधानमंत्री के अनजान होने की मासूम दलील से मनमोहन सिंह के साथ–साथ समूची संप्रग सरकार की विश्वसनीयता धुल चुकी है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार के मुखिया हैं। कल तक जिस देश को अत्यंत ऊर्जावान और उदीयमान सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया सम्मान के भाव से देख रही थी और देश–विदेश के निवेशक यंहा पूंजी निवेश के लिए उत्सुक थे, आज पूरी दुनिया उसे भ्रष्ट देश के रूप में देख रही है। ■

(लेखक भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं)
(दै. जागरण से साभार)

भाजपा बिहार प्रदेश कार्यसमिति बैठक

'भ्रष्टाचार से हुआ कई शासनों का पतन'

भ्रष्टाचार एक बार फिर भारत को गुलामी की राह पर ले जा रहा है। वैशाली गणतंत्र का अंत भी भ्रष्टाचार के कारण हुआ। मौर्य व गुप्त साम्राज्यों के पतन का कारण भी भ्रष्टाचार था और अंतिम मुगल शासन को भी अंदर से भ्रष्टाचार ने जकड़ लिया था।

कांग्रेस या भाजपा का सवाल नहीं है, देश के भविष्य का सवाल है। किसी भी सरकार के लिए भ्रष्टाचार पर काबू पाना जरूरी है। यह बातें मुजफ्फरपुर में आयोजित भाजपा कार्यसमिति में अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सी.पी. ठाकुर ने कहीं। यहां पंडित नेहरू स्टेडियम के शहीद संजय सभागार में कार्यसमिति ने पार्टी की दिशा और रणनीति तय करते हुए कार्यकर्ताओं से बिहार को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का अगुवा बनाने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन का चम्पारण सत्याग्रह हो या जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रांति, जो आंदोलन बिहार से शुरू हुए वही सफल हुए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कुछ वर्षों तक राजनेताओं में त्याग की भावना रही। थोड़े ही दिनों बाद भ्रष्टाचार पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दों से आज जनता को अवगत कराने के लिए 'टू–जी' जैसे जटिल शब्दों को सरल भाषा में समझा जाएगा। महंगाई और कालाधन भी भ्रष्टाचार की उपज है। प्रखंड व गांव स्तर पर बताया जायेगा कि भ्रष्टाचार कैसे और क्यों फैल रहा है? इससे किसको फायदा हो रहा है। डॉ. ठाकुर ने कहा कि बिहार के समग्र विकास के लिए यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तीन साधनों का व्यापक उपयोग करना पड़ेगा। हमारे पास अच्छे दिमाग वाली प्रतिभाएं हैं, उपजाऊ जमीन है और पर्याप्त मात्रा में पानी है। सरकार को इन साधनों पर आधारित विकास का मॉडल बनाना चाहिए। भाजपा कार्यसमिति ने कर्नाटक की तर्ज पर कृषि के लिए अलग बजट बनाने की आवश्यकता बताई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधामोहन सिंह ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में एनडीए सरकार ने बजट में कृषि पर 40 गुना अधिक राशि का प्रावधान किया है, परन्तु अब केन्द्र सरकार को रेल की तरह कृषि का अलग बजट पेश करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रश्न उठाया कि कर्नाटक की जमीन में जलस्तर ऊपर क्यों उठ रहा है, जबकि बिहार में 20 फुट नीचे चला गया है। हम नदियों को जोड़ने की बात तो करते हैं, परन्तु आहर, पईन व तालाबों का संरक्षण जैसा छोटा काम नहीं करते हैं। उत्तर बिहार में मणिका मन जैसे अनेक जलाशय हैं, जिनमें मत्स्य पालन का प्रोजेक्ट शुरू कर बिहार की तकदीर बदली जा सकती है। सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यसमिति में विधायक विनोद नारायण झा द्वारा प्रस्तुत कृषि संबंधी प्रस्ताव में कृषि विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए राज्य व केन्द्र सरकारों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। ■

भाजपा ने लोकहित के मुद्दे उठाए बजट सत्र में

संसद का बजट सत्र आज समाप्त हो गया है। सत्र की समाप्ति तारीख को पांच राज्य विधान सभाओं के लिये आगामी चुनावों के कारण आगे बढ़ाना पड़ा। यह सत्र जवाबदेही का था। सरकार को अपनी गलतियों के लिये उत्तर देना था। भाजपा और अधिकांश विरोधी पार्टियों का प्रमुख उद्देश्य सरकार को उसके गलत कार्यों के लिये उत्तरदायी ठहराना था। सरकार को हर रोज किसी न किसी चीज के लिये कुछ भुगतना पड़ा। उसके उत्तर विश्वास न करने लायक और अपर्याप्त थे। भाजपा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, केन्द्रीय बजट, रेलवे बजट और अनेक अन्य मुददों पर चर्चा का उपयोग सरकार की आर्थिक और राजनीतिक असफलताओं को उजागर करने के लिए किया। मुद्रास्फीति, विशेषरूप से खाद्य मुद्रास्फीति निरन्तर बनी हुई है। सभी समाज कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन असन्तोषजनक है। उन योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत अधिक लीकेज है। सरकार इस सम्बंध में सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाई है।

एक दागदार अधिकारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त करने के पीछे प्रधानमंत्री ही 'प्रीवि' थे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने भाजपा के दृष्टिकोण को सही ठहराया। प्रधानमंत्री ने इसका उत्तरदायित्व लिया परन्तु जवाबदेही की पहचान नहीं कर पाये। इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला है कि लोकसभा में विपक्ष की नेता द्वारा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को यह बताये जाने के बावजूद, कि उनकी पसन्द के व्यक्ति के विरूद्ध एक आपराधिक मामला लम्बित है, एक दागदार अधिकारी की नियुक्ति के लिये उन्होंने जिद्द क्यों की। सरकार को प्राइवेट कम्पनियों को 2 जी स्पेक्ट्रम के आबंटन के बारे में जेपीसी का गठन करने की विपक्ष की मांग के आगे झुकना पड़ा। हम आशा करते है कि समिति तेजी से अपना कार्य करेगी और सच्चाई का पता लगायेगी। तथापि, कुछ राजनीतिक पार्टियां मामले की जांच करने के अलावा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर इसके कार्य में बाधा डालने के लिये बहुत उत्सुक हैं।

गत 25 मार्च, 2011 को नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) श्रीमती सुषमा स्वराज और नेता प्रतिपक्ष (राज्यसभा) श्री अरूण जेटली द्वारा बजट सत्र, 2011 की समाप्ति के अवसर पर जारी प्रेस वक्तव्य

जेपीसी के गठन के प्रस्ताव पर हुई चर्चा से पता चलता है कि सरकार की रणनीति 2008 की गलतियों से मुद्दे को दूसरी ओर मोड़ कर दूसरी ओर ले जाने की थी। संसद के दोनों सदनों में वोट के लिये नोट पर हुई चर्चा में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इसी प्रकार के प्रयास किये। रिश्वतखोरी के मामले की जांच करने के बजाय चर्चा को दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास किया गया कि इस बात का कैसे और क्यों पता चला। सरकार की रणनीति यह है कि भ्रष्टाचार के किसी मामले मे सच्चाई की जांच न कराई जाये। इसके बजाय, ''बस सेंट किट्स'' करें। यह बात स्मरणीय है कि सेंट किट्स वह प्रकरण था जिसमें 1980 के दशक के दूसरे हाफ में कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचापर के आरोप का सामना करना पड़ा था, वेस्ट इंडीस के एक द्वीप सेंट किट्स में बैंक खातों के फर्जी दस्तावेज बनाने शुरू किये गये थे और वी पी सिंह के पुत्र द्वारा धांधली किये जाने का आरोप लगाया गया था।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के घोटालों का राज खुलता जा रहा है। भाजपा इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाती रहेगी।

भाजपा ने इस सत्र में लोकहित और राष्ट्रहित के बहुत सारे मामले उठाये हैं। आन्ध्र प्रदेश में किसानों की समस्या और सोमालिया में बन्दी बना कर रखे गये भारतीय सेलरों की दशा सम्बंधी मुद्दे भी भाजपा ने प्रभावी ढंग से उठाये।

राष्ट्र हित के मुद्दों पर पार्टी ने लीबिया में अमरीकी हस्तक्षेत्र के बारे में भारत सरकार के रवैये का पूर्ण समर्थन किया। भाजपा शुचिता और जवाबदेही दोनों मुद्दों पर अपना अभियान संसद में और संसद के बाहर जारी रखेगी।

प्रत्येक मुद्दे पर हम जो भी कदम उठायेंगे और जो भी रवैया अपनायेंगे वह राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही होगा।■

बायो-फ्यूल देश की प्रमुख आवश्यकता : भाजपा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा प्रधानमंत्री को बायो–फ्यूल पर 25 मार्च 2011 को लिखा पत्र

प्रिय डॉ सिंह,

नमस्कार!

एक शताब्दी से भी अधिक समय से परिवहन, बिजली, घरेलू क्षेत्र आदि के कामों के लिए हाईड्रोकार्बन वाला फॉसिल ईंधन उर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। परन्तु इसकी तेजी से हो रही खपत और इस कारण इसके भण्डारों की कमी आने से पता चलता है कि फॉसिल ईंधन का युग बहुत लम्बे समय तक चल नहीं पाएगा। इसके अलावा भी इस प्रकार का ईंधन वायु प्रदूषण फैलाता है और ग्रीन हाउस गैस (जीएचएस) का प्रमुख साधन बन जाता है जिसके कारण यह माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन में इसका गहरा हाथ रहता है।

इस समय हम 11,09,000 करोड़ रूपए की कुल राशि में से लगभग 7,75,000 करोड़ रूपए का खर्च उठा रहे हैं जो कच्चे तेल के आयात का 34 प्रतिशत भाग बनता है। वर्तमान खपत दर के हिसाब से भारत के तेल भण्डार केवल 20–25 वर्ष ही चल पाएंगे। अतः यही अवसर है कि हम भारत के बायो–ईंधन कार्यक्रम पर विचार करें जिससे बहुत हद तक आयात की निर्भरता कम होगी और हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ पाएंगे।

इसकी तुलना में बायो–ईंधन का पुनः नवीकरण हो सकता है; अतः यह कार्बन ईंधन का पूरक बन सकता है, उनके संरक्षण में मददगार हो सकता है और साथ ही जलवायु के विपरीत प्रभावों को नष्ट कर सकता है। बायो–ईंधन के इस्तेमाल से कई अन्य लाभ मिलते हैं, जिससे रोजगार बढ़ते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी पर्याप्त सुधार होता है, तेल आयात पर निर्भरता कम होने से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है और वायु प्रदूषण भी कम होता है।

जनवरी 2003 में एनडीए सरकार ने भारतीय बायो–ईंधन कार्यक्रम की शुरूआत की थी; उस समय पेट्रोल के साथ 5 प्रतिशत का एथेनाल मिलाना चार राज्यों और चार संघ शासित क्षेत्रों में बाध्यकारी बना दिया गया था। इसी कार्यवधि में बायो–डीजल मिशन को टीबीओ (तेल आधारित वृक्षों) की खेती के अन्तर्गत निर्जन तथा कम–उपजाऊ भूमि की चार लाख हेक्टेयर का जुताई का उद्देश्य बनाया गया था। किन्तु, इसकी आवश्यकता और संभावनाएं होते हुए भी भारत में पिछले छह वर्षों में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है।

एथेनाल और बायो–ईंधन विश्व में लगभग कई देशों में करीब एक दशक से, विशेष तौर पर यूएसए, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय देशों आदि में तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

हमें यह देखते हुए हर्ष होता है कि भारत सरकार ने दिसम्बर 2009 में बायो–ईंधन नीति और इसके कार्यान्वयन कार्यक्रम की शुरूआत की है। परन्तु, पिछले एक वर्ष की प्रगति देखें तो लगता है कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। देश की आवश्यकता को देखते हुए, यह वांछनीय है कि सरकार युद्धस्तर पर देश को बचाने के लिए गम्भीरता से कार्यान्वयन पर जोर दे। इससे जहां एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा की राह पर हम आगे बढ़ेंगे वहीं, दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारी लड़ाई और अधिक शक्तिशाली बनेगी।

भाजपा संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे को नियमित रूप से उठाती रही है। वास्तव में भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री एम.के. अन्ना पाटील के नेतृत्व में बायो ईंधन प्रकोष्ठ का गठन भी किया है। प्रकोष्ठ ने सभी स्टेकहोल्डरों के साथ विचार विमर्श कर बायो–ईंधन कार्यक्रम हेतु एक 'चार्टर आफ डिमांड' (मांग–पत्र) भी तैयार किया है।

मेरा अनुरोध है कि आप सक्रिय रूप से एवं निजी रूप से इस विषय और सम्बन्धित चार्टर ऑफ डिमांड पर विचार करें।

सादर,

भवदीय

नितिन गडकरी

देशहित में, हो भ्रष्टाचार-मुक्त राह कांग्रेस कहे, भ्रष्टाचार ही हमारी राह

& IR;iky

fØकेट इतिहास में भारत ने विश्व विजेता बनकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया। देश–विदेश से भरपूर सराहना हुई, यहां तक कि आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और स्वयं फाइनल की पराजित टीम ने भारतीय टीम, धोनी के नेतृत्व एवं तेंदुलकर की प्रशंसा में छक्के–चौके लगा दिए। इसके साथ ही भारत की इस विश्व विजयी टीम के समाचार के अलावा, आसपास के दिनों में ही विश्व की एक प्रमुख पत्रिका में छपे सर्वे में भारत को भ्रष्टाचार में चौथे स्थान पर रखे जाने की खबर भी छपी, जिस पर कटाक्ष करते हुए एक कार्टून में कहा गया कि देश में अरबों–खरबों के घोटाले वाला यह देश विश्व–विजेता क्यों नहीं बन पाया? कहीं यह 'मैच–फिक्सिंग' का विषय तो नहीं? खैर, चौथे स्थान पर भी भारत का नाम होना एक कलंक है, जो आज के ढेर सारे घोटालों को देखते हुए कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार ने ऐसी सौगात दी है, जिससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाता है।

हाल ही में शुंगलू समिति ने राष्ट्रमण्डल खेलों पर अपनी रिपोर्टें पेश की हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ खेलों से जुड़ी दिल्ली सरकार, आयोजन समिति, केन्द्रीय गृह मंत्रालय और पीएमओ तक पर अनियमितताओं और भारी लूट के आरोप सिद्ध हुए हैं। हालांकि शुंगलु समिति ने एक तरफ तो आयोजन समिति के अध्यक्ष कलमाडी को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कलमाडी पर अनेकों कम्पनियों को नियमों से बाहर जाकर खुले हाथों धन लुटाने के आरोपों से बरी भी नहीं किया है।

शुंगलु समिति की रिपोर्ट आते ही सर्वप्रथम तो दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार पर जिम्मेदारी आती है, फिर भी वह शुगंलु समिति की रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं रखेंगी, जिससे पता चलता है कि समिति की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, वह एकदम सच है। मात्र इतना कह देने से कि शुगंलु समिति का गठन कोई संवैधानिक गठन नहीं था, इससे तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता।

शुंगलु समिति की रिपोर्ट आते ही सर्वप्रथम तो दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार पर जिम्मेदारी आती है, फिर भी वह शुगंलु समिति की रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं रखेंगी, जिससे पता चलता है कि समिति की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, वह एकदम सच है। मात्र इतना कह देने से कि शुगंलु समिति का गठन कोई संवैधानिक गठन नहीं था, इससे तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता। इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए उनका यह कहना कि यह तो एक खामख्याली रिपोर्ट है, इससे उनके झूठ के पाप धुल नहीं जाते हैं। तभी श्रीमती शीला दीक्षित ने खुद जाकर प्रधानमंत्री से मिलीं और अपनी सफाई दी। उधर स्वच्छ छवि से अभिभूत प्रधानमंत्री भी उनकी सफाई सुनकर एकदम चुप्पी साध रखी है और माना जा रहा है कि वे शुंगलु समिति की रिपोर्ट पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। परन्तु अभी हाल में प्रधानमंत्री की टिप्पणी आई है कि विभिन्न विभाग रिपोर्टों पर छानबीन कर रहे हैं। मतलब, इन रिपोर्टों पर वही 'लाल फीताशाही' चलती रहेगी और अन्ततः इसे ठण्डे बस्ते में डाल देने की कहीं अधिक आशंका दिखाई पड़ती है। कहां गया, प्रधानमंत्री का वह वायदा कि हम कॉमनवेल्थ खेलों से जुड़े किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? सहसा ही प्रधानमंत्री अपनी उज्ज्वल छवि भुला कर सम्पूर्ण राजनीति करने में माहिर दिखाई पड़ने लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण ही सीबीआई ने ए. राजा और कुछ अन्य अधिकारियों और कम्पनियों पर हाल में जो प्रथम आरोप पत्र जारी किया है, उसमें कहां तक सीबीआई सफल होगी, इसमें भी लोगों को संदेह लगता है। सीबीआई ने आयोजित समिति के अध्यक्ष, जिन पर लगभग सभी अनियमितताएं करने एवं करोड़ों रूपए की धनराशि लुटाने का आरोप है, आज तक मात्र थोड़ी बहुत पूछताछ कर के उन्हें गिरफ्तार भी न किए जाने से यह आशंका और भी बलवती होती है।

सीबीआई ने अपने प्रथम आरोप पत्र में ही ए. राजा, कुछ अधिकारियों और कम्पनियों पर 30,984 करोड़ रूपए के घोटाले की साजिश रचने का आरोप

लगाया है। यह बात भी जग जाहिर है कि जितनी इस विशाल राशि का पता लगा है, उससे भी और कहीं अधिक राशि का षड्यंत्र होना लाजिमी है, जिसके बारे में अभी भी सीबीआई को कुछ पता नहीं चला है। राष्ट्रमण्डल खेलों में जिस 70,000 करोड़ रूपए से अधिक राशि का देश को नुकसान हुआ है, आखिर वह देश के खजाने में कैसे लौटेगी, इसका तो दूर–दूर तक भी कुछ पता नहीं है। यही नहीं कॉमनवेल्थ खेलों के बाद जिस प्रकार से खेलगांव के लिए उच्च दामों पर खरीदे गए टीवी, अन्य उपकरणों आदि की जैसी दुर्दशा हो रही है, वह किसी से छिपी नहीं है। आप इस राशि को भी बट्टे खाते में डाला समझिए।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियां देने में एक मात्र पार्टी भाजपा रही है, जिसने पूरे देश में यह आंदोलन छेड़ा हुआ है। भाजपा अपने स्थापना दिवस 6 अप्रैल से इसे और भी तेज गति से चला कर पूरे देश को जागरूक करने की पहल भी कर रही है।

भ्रष्टाचार न केवल देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व में भारत की छवि को कलंकित करने का ऐसा काम कर रही है जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इधर कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार को तो भ्रष्टाचार के खिलाफ चिंतित होने के अलावा कोई उपाय न करने की ठानी हुई है। काला धन विदेशों से देश में आए, इस पर भी इस सरकार को जरा चिंता नहीं है, क्योंकि वह तो विदेशों से हुई संधियों के नाम पर चुप हो जाना पसंद करती है और यह भी नहीं देखती कि ऐसी ही संधियों के बावजूद अमरीका तथा कई अनेक यूरोपीय देशों ने अपने देश में काला धन लौटा कर दिखाया है। क्या भारत सचमुच दुर्बल है– सरकार यही मानती है।

इधर 5 अप्रैल से प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध जन लोकपाल विधेयक लाने पर अनशन शुरू कर दिया है क्योंकि वे तथा उनके साथ स्वामी अग्निवेश, किरण बेदी, अरविन्द केजरीवाल आदि प्रबुद्धजन एवं अनेकों लाखों करोड़ों लोगों को सरकार द्वारा लाए जा रहे नख–शिखदंत विहीन लोकपाल बिल पर भरोसा ही नहीं है। लचर किस्म के बिल लाना कांग्रेस सत्ताधारियों की बड़ी पुरानी आदत है। आप जरा दल–बदल कानून को ही देखिए, उसमें ऐसी धाराएं हैं, (उदाहरण स्वरूप किसी पार्टी की संख्या के एक–तिहाई लोगों के अलग होने के बाद ही दल–बदल विधायक सांसद माना जाना) कि कभी–कभी तो ये लोग पूरा कार्यकाल ही बिता देते हैं और अदालत का निर्णय नहीं हो पाता है। यह सब कुछ जानबूझ कर किया जाता है। कांग्रेस का नेतृत्व चुनाव घोषणा–पत्र बनाते समय लोगों को गुमराह करने का साधन बन गया है, जबकि लोकतंत्र में तो घोषणा–पत्र का दर्जा बाइबिल के समान होता है।

सच यही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार मिटाना ही नहीं चाहती। स्वातंत्र्योत्तर काल का पूरा इतिहास ही कांग्रेस के भ्रष्ट आचरणों के किस्सों से भरा पड़ा है। लोकपाल विधेयक लाने पर कांग्रेस ने 2004 के घोषणापत्र में शामिल किया था। कांग्रेस–नीत यूपीए गठबंधन का पूरा कार्यकाल बीत गया। क्या इसे कांग्रेस का लोगों के साथ विश्वासघात और छल नहीं कहेंगे?

अब जाकर कांग्रेसनीत यूपीए–II का एक वर्ष का कार्यकाल बीत जाने पर जिस प्रकार का 'लो–प्रोफाइल' लोकपाल विधेयक पेश करने की कांग्रेस ने अधमरे मन से बात की है, वह तो विश्वासघात और छल–कपट की सारी सीमाएं लांघ गई है। जैसा कि अभी तक इसके प्रावधानों के कुछ अंश सुनने में आए हैं, उनसे पता चलता है कि लोकपाल अनौपचारिक होगा और इसकी अध्यक्षता वित्तमंत्री करेंगे। अनौपचारिक लोकपाल विधेयक का मतलब ही यह है कि इस समिति के पास कोई अधिकार नहीं होंगे और वित्तमंत्री की अध्यक्षता का मतलब है कि सरकार जिसे चाहे भ्रष्टाचार के दायरे में मान ले, और जिसे न चाहे उसे भ्रष्ट–मुक्त रखने का खुला खेल खेले। शायद छह सालों से अधिक समय बीत जाने के कारण घोषणा पत्र में किए गए वायदे पर कांग्रेस के लिए यह विधेयक लाना जरूरी हो गया है।

स्वतंत्रता–पूर्व एक महान पुरूष 'महात्मा गांधी' थे जिन्होंने अपने अहिंसात्मक आंदोलन तथा अनशन के माध्यम से भारत से अंग्रेजों का पत्ता साफ कर दिया था। आज सौभाग्य से

यह बात समझ से परे है कि भ्रष्टाचार जैसे विषय पर अण्णा जी को अनशन पर बैठना ही क्यों पड़ा? क्यों कांग्रेस और सरकार का रवैया इसे जन–लोकपाल विधेयक बनाने में झिझका? प्रधानमंत्री का अब यह कहना कि यह लोकतंत्र की जीत है, क्या हास्यास्पद नही लगता? निश्चित ही यह जनता की जीत है लोकतंत्र की जीत है और बेहतर होता कि कांग्रेस तथा सरकार अण्णा हजारे, जिन्होंने पांच दिन तक अनशन का दुख भोगा, यह बात स्वीकार करते और जनता से क्षमा मांगते कि हमने आखिरी दम तक लोकतंत्र का नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और हम सचमुच शर्मिंदा हैं।

स्वतंत्रता के बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले एक प्रख्यात प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे सामने आए हैं, और वे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का बीड़ा उठा कर अनशन पर बैठे हैं।

कमाल यह है कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस–अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी एक तरफ अण्णा हजारे से अनशन समाप्त करने की अपील करते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता सिंघवी साहब उन्हें लोगों द्वारा भड़काने की बात कर उनका अपमान करते हैं। हजारे ने ठीक ही कहा कि अनशन जैसे गम्भीर विषय पर क्या उन्हें कोई भड़का सकता है? कितना बड़ा उपहास है? उधर श्रीमती अम्बिका सोनी ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर मंथन होना चाहिए। भ्रष्टाचार पूरे देश को लूट रहा है, खा रहा है, ऐसे में मंथन नहीं, कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है जिसमें विकट भ्रष्टाचार के मामलों में तो फांसी देने जैसा प्रावधान भी हो तो बुरा नही है। बल्कि विकट भ्रष्टाचार क्या है, इसकी परिभाषा भी इन प्रावधानों में शामिल रहे, जिससे ऐसे भ्रष्टाचारियों का कोई बचाव ही न हो पाए। मंथन करने का अर्थ है विवाद पैदा करना। क्या यह भी विवाद का विषय बनना चाहिए?

आखिरकार सरकार इस बात पर तो झुक गई है कि जन लोकपाल विधेयक पेश किया जाएगा और अगले सत्र में ही पेश भी होगा तथा जनता–सरकार की 50–50 प्रतिशत की भागीदारी होगी, परन्तु वह इसका नोटिफिकेशन निकालने और अनौपचारिक स्थिति को समाप्त करने पर राजी नहीं हैं। स्पष्ट है कि अण्णा हजारे भ्रष्टाचारियों को मिटाने और दण्ड दिलाने के लिए कृतबद्ध हैं तो कांग्रेस तथा केन्द्र सरकार भ्रष्टाचारियों को गले लगाने के मूड में है। केन्द्र सरकार मंत्री को ही अध्यक्ष बनाने पर तुली है तो अण्णा का कहना है कि कोई पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष बने। बताइए, मंत्री न्याय कर सकता है या कोई जज, सच तो यह है कि कोई भी ऐसा पद जिस पर निष्पक्ष न्याय की आवश्यकता हो, उस पर केन्द्र सरकार का दखल होना ही नहीं चाहिए।

किन्तु 'सत्यमेव जयते'– अण्णा हजारे विजयी होंगे– और आज पांच दिनों के अनशन के बाद अण्णा हजारे की समस्त मांगें स्वीकार होने के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन की कॉपी प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने अनशन समाप्त किया है, जिसके बारे में इस जीत को जनता की जीत और लोकतंत्र की जीत बताया है। पर, यह बात समझ से परे है कि भ्रष्टाचार जैसे विषय पर अण्णा जी को अनशन पर बैठना ही क्यों पड़ा? क्यों कांग्रेस और सरकार का रवैया इसे जन–लोकपाल विधेयक बनाने में झिझका? प्रधानमंत्री का अब यह कहना कि यह लोकतंत्र की जीत है, क्या हास्यास्पद नही लगता? निश्चित ही यह जनता की जीत है लोकतंत्र की जीत है और बेहतर होता कि कांग्रेस तथा सरकार अण्णा हजारे, जिन्होंने पांच दिन तक अनशन का दुख भोगा, यह बात स्वीकार करते और जनता से क्षमा मांगते कि हमने आखिरी दम तक लोकतंत्र का नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और हम सचमुच शर्मिंदा हैं। ■

गुलाम कश्मीर में चीनी सैनिक : विदेश मंत्री कृष्णा से मिले तरुण विजय

भाजपा सांसद तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री तरुण विजय ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चीनी सैनिकों की उपस्थिति के बारे में विदेशमंत्री श्री एस.एम. कृष्णा से 7 अप्रैल को वार्ता की और देश की सुरक्षा को चीनी खतरे के बारे में जनता की चिन्ताओं से अवगत कराया।

श्री कृष्णा ने श्री तरुण विजय को आश्वासन दिया कि विदेश मंत्रालय इस विषय पर चीन के सम्पर्क में है और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चीनी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सेना हर प्रकार से स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं तथा इस मामले में किसी भी घबराहट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार का कहना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वे विकास कार्य हेतु सहायता कर रहे हैं, इस पर श्री विजय ने कहा कि चीन पर भरोसा किये बिना हमें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए तथा चीन के शिखर नेतृत्व से इस बारे में वार्ता करनी चाहिए।

श्री विजय और श्री कृष्णा इस बारे में सहमत थे कि सावधानी का स्तर ऊंचा रखते हुए चीन के साथ दोस्ताना रिश्ते बढ़ाते रहने की जरूरत है। चीन के बारे में आम भारतीय को अधिक से अधिक जानकारी मिलनी चाहिए तथा ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को चीन की यात्रा पर जाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। श्री विजय ने श्री कृष्णा को बताया कि भारत में लद्दाख सीमा पर पेंगोंग्त्से झील का एक तिहाई भारतीय सीमा में तथा दो तिहाई लाईन ऑफ एक्च्यूअल कंट्रोल के पार चीनी कब्जे में है। वहां भारतीय सेना के पास झील की पेट्रोलिंग के लिए सिर्फ दो पुरानी पेट्रोल नौकाएं हैं, जबकि चीन के पास 22 आधुनिकतम ऑटोमेटिक पेट्रोल नौकाएं हैं। ■

शुगंलु समिति की रिपोर्टों को खारिज करने का शीला दीक्षित को अधिकार नहीं

प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व सीएजी श्री वी.के. शुंगलु की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी दूसरी और तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इससे पहले 31 जनवरी 2011 को अपनी पहली रिपोर्ट दी थी। पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए पैनल का कार्यकाल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया था।

पहली रिपोर्ट में ब्राडकास्टिंग अधिकारों सम्बंधी अनियमितताओं का उल्लेख था। दूसरी रिपोर्ट में खेलगांव और तीसरी रिपोर्ट में सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी अनियमितताएं हैं।

अन्य बातों के अलावा पहली रिपोर्ट में प्रसार भारती के सीईओ श्री बीएस बाली तथा पूर्व महानिदेशक (दूरदर्शन) श्रीमती अरूण शर्मा के खिलाफ सभी प्रकार की भूलचूकों के लिए आईपीसी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।

कांग्रेस पार्टी ने शुगंलु समिति की पहली रिपोर्ट में निष्कर्षों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

किन्तु मीडिया के जरिए रिपोर्ट लीक होने के कुछ ही घण्टों में दूसरी तथा तीसरी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां और जानकारी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट का 'पूर्णतः अनुचित, विरोधाभासी और ''तथ्यों से परे'' बताते हुए कूडेदान में डालने लायक बताया है। 28 मार्च 2011 को दिल्ली मंत्रिमण्डल की बैठक में इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और आरोप लगाया कि ''रिपोर्ट एक तरह से सरकार के खिलाफ लांछन'' है।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा शुंगलु समिति रिपोर्ट पर 29 मार्च 2011 को जारी प्रेस वक्तव्य

इस प्रकार की बातें तब कही जा रही है कि जब मुख्यमंत्री का दावा है कि उन्हें रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव को यह रिपोर्ट 28 मार्च को प्राप्त करने की उम्मीद थी और मुख्यमंत्री की टिप्पणी है कि ''लेकिन शुक्रवार को ही इसे वेबसाइट पर डाल दिया गया था। निश्चित ही हमें भी अपने दृष्टिकोण पेश करने का मौका मिलना चाहिए। फिर भी शीला दीक्षित की केबिनेट को इसे 'तथ्यों से परे' बता कर खारिज करने से रोकने वाला कोई नहीं था।

पहली रिपोर्ट के आधार पर प्रसार भारती के कुछ चुनिंदा अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, जबकि श्री सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्री कलमाड़ी कांग्रेस संसदीय दल के सचिव पद से हटाना उन पर लगे आरोपों का कोई मतलब नहीं है।

शुंगलु समिति ने निर्माण कार्यों में देरी के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है जिसके कारण ''मिलीभगत आंशिक नीलामी की बोली'' और ''दस्तावेजों की हेराफेरी'' हुई।

भाजपा मांग करती है:-

प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति जैसी भी हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसे खारिज कर सकती हैं। केबिनेट ने इस रिपोर्ट को बिना पढ़े ही खारिज कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेसी सरकार पर विभिन्न प्रकार की भूल–चूकों के आरोप हैं। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष को इस प्रकार के अतिक्रमण पर खुल कर अपनी राय प्रगट करनी चाहिए।

निर्माण की लागत और उपकरणों की खरीददारी में बहुत अधिक मूल्य चुकाए गए। योजना आयोग, नगर विकास मंत्रालय तथा खेल मंत्रालय ने इन मूल्यों का अनुमोदन किया था। बड़े–बड़े बिल्डरों को बड़े सुनियोजित ढंग से बाहर खड़ा कर दिया गया था, जिससे ''मिलीभगत की नीलामी बोली'' लगी। किसने और किस आधार पर लागत के अधिक मूल्यों का अनुमोदन किया? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? दोनों मंत्रालयों को अपनी भूमिका के बारे में पाक–साफ होना चाहिए।

कॉमनवेल्थ खेलों सम्बन्धी सभी मामलों को जांच के लिए तुरंत ही एक ही स्थान पर लाना आवश्यक है। कार्रवाई के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। ■

मनमोहन सिंह का नो-बाल, शून्य पर हुये आऊट

& vEck pj.k of'k"B

Xत 30 मार्च 2011 को मोहाली आये हमारे प्रधान मन्त्री डा0 मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री श्री सईद यूसुफ रज़ा गिलानी। पर वह न तो उन दर्शकों का ही मन जीत सके जो भारत व पाकिस्तान से हज़ारों की संख्या में भारत व पाकिस्तान के बीच विश्व कप के लिये हो रहे सेमी–फाइनल का आनन्द लेने पहुंचे थे और न ही उनका जो अपने–अपने देश में इसका आनन्द उठा रहे थे और मनमोहन–जिलानी के बीच के वार्तालाप पर नज़र रखे हुये थे। यह इस लिये भी कि वह तो केवल दो अति महत्वपूर्ण दर्शक ही थे जो मैच के आनन्द के साथ बीच–बीच में दोनों देशों के बीच आपसी सम्बंधों की फुसफुसाहट भी करते जा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्रधान मन्त्री डा0 मनमोहन सिंह तो एक अन्धे प्रेमी की तरह पाकिस्तान के साथ हर सूरत में वार्तालाप जारी रखने के पक्ष में हैं। इस बारे उनकी भावना और इच्छाशक्ति का कोई सानी नहीं है। हालांकि यह सब जानते हैं कि यह भावना एकतरफा है। पाकिस्तान ने उनकी भावनाओं का मान रखते हुये कभी उतनी उदारता अथवा गर्मजोशी नहीं दिखाई। वह बार–बार यही दोहराते रहते हैं कि वार्तालाप हर सूरत में जारी रहना चाहिये।

पर पाकिस्तान के साथ पिछले 63 से अधिक वर्षों में कब विचारों का आदान– प्रदान नहीं हुआ? 1965 और 1971 की दोनों लड़ाइयों के बाद ताशकन्द और शिमला में वार्तालाप हुआ। 1966 में ताशकन्द और 1972 में शिमला समझौता हुआ। तब भी शान्ति, सद्भाव, भाईचारे की उम्मीदों के बहुत पुल बांधे गये। पर वस्तुतः नतीजा क्या निकला? वही ढाक के तीन पात। आज यह दोनों समझौते एक ऐसे इतिहास का पन्ना बन चुके हैं जिसमें फायदे में केवल पाकिस्तान ही रहा और भारत के हाथ लगे इन समझौतों के मात्र कुछ पन्ने जिनका महत्व किसी रद्दी के टुकड़े से अधिक नहीं है। हमने कठिनतम परिस्थितियों में युद्ध के मैदान में अनमोल शहादतें देकर जो कुछ जीता था उसे सहर्ष वार्ता की मेज़ पर बैठकर तश्तरी में ससम्मान पाकिस्तान को भेंट कर दिया। कश्मीर जैसी जटिल समस्या को सुलझाने का सुअवसर हमने जानबूझ कर अपने हाथ से गंवा दिया।

वार्तालाप का विकल्प नहीं

साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि अन्ततः हर संघर्ष का, हर झगड़े का, हर युद्ध का समाधान केवल वार्तालाप ही है। उसका कोई विकल्प नहीं है। यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिये। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि दूसरा पक्ष भी उस प्रेम भावना और सद्भाव का उतना ही आदर–सत्कार करे। एक–तरफा मामला सदा असफलता को न्यौता देना होता है। कई बार तो व्यक्ति निराशाभाव से इतना अधिक ग्रसित हो जाता है कि वह आत्महत्या तक कर बैठता है।

सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आसिफ ज़रदारी और प्रधान मन्त्री श्री गिलानी को मोहाली में भारत–पाक क्रिकेट सेमी–फाइनल के लिये आमन्त्रित कर एक तीर से दो निशाने साधने का प्रयास किया था। एक तो यह कि इस बहाने एक बार फिर भारत–पाक वार्ता का रास्ता प्रशस्त हो जाता और दूसरी ओर भारत की जनता का ध्यान नये से नये घोटालों व अदालतों में यूपीए सरकार की हो रही फज़ीहत से ध्यान हट जाता।

अपने तौर पर कांग्रेस को भी आशा थी कि मोहाली में होने वाली बातचीत से हवाना में भारत–पाक ने जो हाथ मिलाया था और क्षणिक शरम–अल–शेख में गले मिलने से देश में हुई फज़ीहत के काले धब्बे जनता के स्मृतिपटल से मिट जायेंगे।

हमारे प्रधान मन्त्री भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि वह इस सत्य से अनभिज्ञ हों। 26/11 के बाद पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता के निरर्थक प्रयास पर अपना पैसा, समय व शक्ति बर्बाद करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित हो उठता। पाकिस्तान ने तो अभी तक इतना भी संकेत नहीं दिया है कि वह

सीमापार से आतंकी गतिविधियों पर रोक लगा कर सत्यनिष्ठा से आपसी सम्बन्ध सुधारना चाहता है।

ब्रेकिंग न्यूज़ का मोहजाल

ब्रेकिंग न्यूज़ के लिये मीडिया का लालच व मोहजाल असीमित है। इसकी भूख और प्यास तो कभी मिटती ही नहीं। इसीलिये मीडिया ने भी भारत की इस क्रिकेट डिप्लोमेसी के इस गुब्बारे में हवा भर कर इसे इतना ऊंचा उछाल दिया कि ऐसा लगने लगा मानो इस बातचीत से दोनों देशों के बीच चमत्कारों की झड़ी लग जायेगी। उन्होंने जनता का ध्यान मोहाली क्रिकेट मैदान से हटा कर उस वीवीआईपी गैलरी पर केन्द्रित कर दिया जिसमें बैठकर दोनों प्रधानमन्त्रियों ने मैच देखना था। मीडिया ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि मैच देखते–देखते दोनों प्रधानमन्त्री ऐसा करिश्मा खड़ा कर देंगे कि सेमी–फाइनल में जीत–हार का कोई महत्व ही नहीं बचेगा।

क्रिकेट डिप्लोमेसी

डा0 मनमोहन सिंह की इस पहल को बहुत बड़ी सम्भावनाओं में छिपी क्रिकेट डिप्लोमेसी की संज्ञा दी जा रही थी। इसमें कांग्रेस व मीडिया दोनों का साझा स्वार्थ था। एक को विशेष समाचार मिल जाता तो दूसरे को समाचारों में छाये रहने का सुअवसर। यह तो चारों ओर से घिरी कांग्रेस के लिये ईश्वरप्रदत्त सुअवसर था।

क्रिकेट या अन्य किसी क्रीड़ा व राजनीति या कूटनीति में कुछ भी साझा नहीं है। क्रीड़ा तो खेल की उदार, निष्कपट मैत्रीपूर्ण स्पर्धा भाव से ओतप्रोत होती है जबकि राजनीति व कूटनीति में तो इन सद्गुणों का अभाव ही रहता है। सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता का तो इसमें कोई काम ही नहीं। कूटनीति तो अपना उल्लू सीधा कर दूसरे को नीचा दिखाने की कला हे। कूटनीति तो इतनी जटिल चीज़ है जिसमें कहने का मतलब वह नहीं होता जो कहा जाता है और जो मतलब होता है वह कहा नहीं जाता।

यह भी सच है कि दो देशों के बीच खेल प्रतियोगितायें आपसी सद्भाव, भाईचारे व दोस्ती को बढ़ावा देती हैं। पर यह दो सरकारों के बीच सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं डालतीं। जो पाकिस्तानी भाई मोहाली में मैच देखने आये थे भारत के प्रति उनके उद्गार उनकी पाकिस्तान के रवैया से कहीं भिन्न थे।

पिंग पौंग कूटनीति

शायद यह पहला ही अवसर था जब आपस में दुश्मनी का भाव रखने वाले दो देशों के बीच सौहार्द का माहौल पैदा करने में खेलकूद किसी प्रकार कारगर सिद्ध हुआ। जापान में अपने प्रवास के दौरान चीन व अमरीका की टेबल टेनिस टीमें आमने सामने हुई और दोनों ने आपस में हाथ मिला कर एक दूसरे को उपहार भी दिये। चीन ने अमरीकी टेबल टेनिस टीम को चीन आने का निमन्त्रण भी दिया। इस प्रकार अमरीका की टेबल टेनिस टीम 1971 में पहली बार चीन गई और मैच खेला। इस घटना ने अमरीका और चीन के बीच आपसी मेलजोल पैदा करने का रास्ता प्रशस्त किया। तब इसे ''पिंग पौंग कूटनीति'' की संज्ञा दी गई।

पर कोई भी खेल कभी दो देशों के बीच समस्याओं के समाधान की दवा नहीं बन पाया है, खासकर भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच के कटु सम्बन्धों को मधुर बनाने में। यदि ऐसा सम्भव होता तो देश आपस की समस्यायें हल करने के लिये कूटनीति की ढाल अपनाने की बजाय खेल का हथियार ही अपनाते।

यही हुआ भारत और पाकिस्तान के साथ भी। मीडिया का गुब्बारा भी आशा के विपरीत बहुत जल्दी फट गया। एक ओर भारत और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री मैच का आनन्द उठा रहे थे और हंस–खेल कर आपसी समस्याओं को हल करने के लिये बातचीत कर रहे थे वहीं दूसरी ओर दिल्ली और इस्लामाबाद में दोनों देशों के राजदूत एक–दूसरे पर अपने कर्मचारियों को ज़बरदस्ती आरोपित कर परेशान किये जाने के आरोप जड़ते जा रहे थे। इस समाचार को दोनों देशों ने एक दिन के लिये बाहर न आने दिया ताकि मोहाली का माहौल जो पहले ही अधिक खुशनुमा न था वह और भी न बिगड़ जाये। संक्षेप में यही निकला हमारे प्रधानमन्त्री महोदय की 'क्रिकेट कूटनीति' का करिश्मा।

हालांकि दोनों प्रधान मन्त्रियों के बीच होने वाली बातचीत का एजेण्डा विधिवत तैयार किया गया था पर अन्त में दोनों ने न कोई संयुक्त वक्तव्य या संयुक्त मीडिया वार्ता भी नहीं की।

''जीत क्रिकेट की''

अन्त में पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री श्री गिलानी ने बस इतना कहाः ''इस में किसी की जीत या हार नहीं है। यह तो क्रिकेट के खेल की विजय है।'' उन्होंने खड़े होकर मैच के निष्कर्ष का ताली बजा कर स्वागत किया। यह भी कहा कि प्रधानमन्त्री डा0 मनमोहन सिंह के साथ कश्मीर समेत हर मुद्दे पर बात हुई। भारत की विदेश सचिव श्रीमती निरूपमा राव ने बातचीत की समीक्षा में कहा कि दोनों प्रधानमन्त्रियों की बैठक स्वभाव में क्रिकेट ही थी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने तो राष्ट्र को पहले ही सचेत कर दिया था कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के इस ड्रामे से वह ज़्यादा उम्मीदें न बांध बैठें। हुआ भी यही। डा0 मनमोहन सिंह खाली हाथ गये थे और खाली हाथ ही लौटे। ■

(लेखक भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं।)

उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था

Mk- f'ko 'kfDr cDlh

14 अप्रैल 2011 को डा. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर को उनकी 120वीं जयंती पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र उन्हें भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत तथा एक प्रखर दलित विचारक के रूप में स्मरण करता है। बाबासाहेब बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व प्रसिद्ध कोलम्बिया विश्वविद्यालय तथा लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स से कानून, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र पर अपने अध्ययन एवं शोध द्वारा अनेकों उपाधियों तथा पीएचडी से विभूषित बाबा साहेब ने एक बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक नेता के रूप में अनेक विषयों पर निर्भीक होकर अपने विचार प्रकट किए। उनके विचारों एवं लेखन एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक बुद्धिजीवी, एक राष्ट्रवादी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति तथा ऐसे ही उनके विभिन्न रूप उभरकर सामने आते हैं। एक राजनीतिज्ञ एवं जननेता के रूप में बाबा साहेब उन विषयों को उठाते रहे जो दूरदृष्टि से परिपूर्ण एवं एक समरस समाज की स्थापना से प्रेरित थे। फलतः अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक सुधार के विषयों पर समर्थन प्राप्त कर आंदोलनात्मक धार को तेज करने हेतु कठोर रवैया अपरिहार्य था ताकि ये विषय सामाजिक–राजनीतिक बहस के केन्द्र में आ सकें। एक बुद्धिजीवी के रूप में उन्होंने अनेक ज्वलंत विषयों पर विद्वत्तापूर्ण एवं शोधपरक विचार रखे जो आज भी प्रासंगिक हैं।

बाबासाहेब का जन्म 14 अप्रैल 2011 को मऊ (अब मध्यप्रदेश में) में एक महार परिवार में हुआ। उनका परिवार मूलतः वर्तमान के महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नागिरी जिला में स्थित

अम्बावडे नगर का रहने वाला था। अपने छात्र जीवन में विद्यालय में उन्हें नीची समझे जाने वाले महार जाति का होने के कारण अनेक प्रकार के भेदभाव सहने पड़े परन्तु इससे उनका उच्च शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प और अधिक दृढ़ हुआ। एलफिन्सटन कॉलेज के छात्र के रूप में बड़ौदा के गायकवाड शासक सयाजीराव तृतीय के द्वारा अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें 25 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई। वे पीएचडी की पढ़ाई के लिए अमेरिका गये तथा अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में इस उपाधि को अर्जित किया। वापस आकर उन्होंने बड़ौदा राज्य की सेवा में अपना योगदान दिया तथा साथ ही तभी भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव तथा अस्पृश्यता के विरूद्ध संघर्ष शुरू किया। उनकी सक्रियता तथा वंचित एवं दबे–कुचले समाज के हित का बौद्धिक रूप से प्रतिपादन करने की उनकी क्षमता ने शीघ्र ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व बना दिया।

अब तक बाबा साहेब के विचारों का अध्ययन एक विशेष संदर्भ में किया गया है जिससे उन्हें भारतीय समाज के वंचित–शोषित वर्गों के नायक के रूप में विचित्र किया जाता है। उन्हें भारत के संविधान निर्माता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने भारत में एक ऐसे उदारवादी लोकतंत्र की नींव रखी जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी राज्य का सपना साकार कर सके।

परन्तु उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं का अध्ययन अभी भी होना शेष है। उनका एक विचारक एवं बुद्धिजीवी के रूप में योगदान, विभाजन के समय जनसंख्या आदान–प्रदान का उनके द्वारा वकालत, भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक स्वरूप को बचाने के उनके प्रयास, एक राजनीतिक ही नहीं वरन् आध्यात्मिक कदम, उनके द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया जाना उनके द्वारा इस्लाम, ईसाइयत तथा मार्क्सवाद को खारिज किया जाना और ऐसे ही उनके व्यक्तित्व के और भी कई अन्य आयाम जिस पर अभी भी अध्ययन एवं शोध की संभावना है।

संविधान के प्रारूप की तृतीय पाठ पर भाव विभोर हो अपने सम्बोधन में

बाबासाहेब ने कहा था, ''26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या वह स्वतंत्र रह पायेगा अथवा पुनः उसे खो देगा? यह पहला विचार था जो मेरे मस्तिष्क में आया। ऐसा नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। गौर करने लायक बात यह है कि उसने वह स्वतंत्रता एक बार खो दी जो उसके पास थी। क्या वह दुबारा इसे खो देगा?

आगे वे अपने प्रश्नों का स्वयं उत्तर देते हैं। वे कहते हैं की उनकी आशंकाओं का जड़ भारत के इतिहास में है जब अपने ही लोगों के हाथों धोखे के कारण देश को पराजय का अपमान सहना पड़ा था। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ''मुझे इस बात से उतनी तकलीफ नहीं होती कि भारत ने एक बार अपनी स्वतंत्रता खो दी थी परन्तु इस बात से मुझे अधिक तकलीफ होती है कि ऐसा देश के अपने ही लोगों के द्वारा दिए गये धोखे एवं विश्वासघात से संभव हुआ। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण के दौरान राजा दाहिर के सेना नायकों ने मोहम्मद बिन कासिम के गुर्गों से रिश्वत खाकर राजा दाहिर के पक्ष में युद्ध करने से इंकार कर दिया। वह राजा जयचन्द ही था जिसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण कर पृथ्वीराज के विरूद्ध युद्ध का न्यौता दिया तथा अपना तथा सोलंकी राजाओं के समर्थन का आश्वासन दिया। जब हिन्दुओं की स्वतंत्रता के लिये शिवाजी युद्धरत थे, अन्य मराठा सरदार तथा राजपूत राजा मुगल सम्राटों का साथ दे रहे थे। जब अंग्रेज, सिक्ख राजाओं का ध्वस्त करने में लगे थे, उनके मुख्य सेना नायक गुलाब सिंह चुपचाप बैठे रहे तथा सिक्ख राजा को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। 1857 में जबकि भारत में अधिकांश भागों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए युद्ध की घोषणा कर रखी थी, सिक्ख पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देखते रहे।''

भारत के लोकतांत्रिक पद्धति अपनाने, लोकतांत्रिक संविधान के भारत में कारगर होने तथा भारत के एक लोकतंत्र के रूप में सफल अथवा असफल होने की संभावना जैसे प्रश्नों पर उनका बड़ा ही ठोस एवं सटीक तर्क था। उन्होंने कहा, ''ऐसा नहीं है कि भारत को यह पता नहीं कि लोकतंत्र क्या है। एक समय था जब भारत में अनेक गणराज्य थे वह भी तब जबकि साथ–साथ राजतंत्र भी हुआ करता था। वे या तो निर्वाचित होते अथवा सीमा की मर्यादा में बंधे होते थे। वे कभी भी एकाधिकारपूर्ण नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि भारत को संसद अथवा संसदीय नियम का ज्ञान नहीं था। बौद्ध भिक्षुओं के संघों के अध्ययन से पता चलता है कि ना केवल संसद थे– क्योंकि संघ कुछ और नहीं बल्कि संसद ही थे– वरन् संघ आधुनिक युगीन संसदीय प्रणाली के सभी नियम–कानून का भी पालन करते थे। उनमें बैठने की व्यवस्था, निंदा प्रस्ताव, कोरम, सचेतक, मतगणना, मतपत्र, नियमन आदि संबंधी नियम थे। हालांकि संसदीय प्रणाली के ये नियम बुद्ध के द्वारा संघों की बैठकों के लिए लागू किए गये थे, परन्तु उन्होंने इन्हें उस समय के राजनीतिक सभाओं जो देश में तभी प्रचलित थे उनसे लिया होगा।''

लोकतांत्रिक आधार पर सरकार चुनने की प्रक्रिया में निहित विभाजन एवं आपसी विद्वेष के खतरे को समझते हुए बाबासाहेब देश की एकता एवं अखंडता को हर हाल में बचाना चाहते थे। समाज में मौजूद विभाजनकारी तत्वों को वे समझते थे परन्तु उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पूर्ण विश्वास था क्योंकि वे भारतीय मानस एवं परंपराओं से प्राचीन काल से ही पूर्णतः जुड़े हुए थे। भारत की जनता को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, ''क्या इतिहास स्वयं को दोराहयेगा? यह बात मुझे चिंता से भर देती है। यह चिंता तब और भी अधिक गहरी हो जाती है जब हम पाते हैं कि जाति–पाति के रूप में मौजूद हमारे पुराने दुश्मन के साथ–साथ अब विपरीत विचार वाले अनेक राजनीतिक दल भी देश में विद्यमान होंगे।

क्या भारतीय अपनी प्रतिबद्धताओं से ऊपर देश को रखेंगे अथवा प्रतिबद्धताओं को देश के ऊपर रखेंगी? मुझे पता नहीं परन्तु इतना निश्चित है कि दल यदि अपनी प्रतिबद्धताओं को देश से ऊपर रखेंगे तब देश की स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जायेगी और हो सकता है कि हम हमेशा के लिए अपनी स्वतंत्रता खो दें। हम सबों को इस प्रवृत्ति के विरूद्ध दृढ़ता से खड़े रहना होगा। हमें अपनी स्वतंत्रता को अपने खून की अंतिम बूंद तक बचाये रखने का संकल्प लेना होगा।''

एक राष्ट्रवादी के रूप में बाबासाहेब ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा। वंचितों एवं शोषितों के हित में निरंतर आवाज उठाते रहने के कारण बाबासाहेब को केवल दलित नेता के रूप में देखा जाने लगा जबकि उनके अन्य योगदानों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका है। बाबा साहेब एक जननेता थे, राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतक, बुद्धिजीवी, ऊंचे दर्जे के विद्वान तो थे ही साथ ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़े एक राष्ट्रवादी भी थे। आज जबकि राष्ट्र निर्माण में उनके योगदानों के लिए देश उनके प्रति कृतज्ञ है, उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर भी अध्ययन एवं शोध की आवश्यकता है।■

मध्य प्रदेश के सभी 55 संगठनात्मक जिलों के मंडलों में विचार गोष्ठियां आयोजित की गयीं

& lokknnkrk }kjk

Hkkरतीय जनता पार्टी के 31वें स्थापना दिवस पर पं. दीनदयाल परिसर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में 6 अप्रैल को पं.दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ध्रुवनारायण सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्य आधारित विचार दर्शन के कारण ही देश के अन्य दलों से अलग पहचानी जाती है। उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा तक भारतीय जनता पार्टी ने देश को नई पहचान दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद रघुनंदन शर्मा ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जी एवं डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के आदर्शों और प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को नई पहचान दी।

पंचनिष्ठा पर आधारित राजनीतिक जीवन का अनुसरण करें : प्रभात झा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री प्रभात झा ने पार्टी के 31वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें पार्टी की पंचनिष्ठा और एकात्ममानववाद पर आधारित राजनीतिक जीवन का अनुसरण करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्राण–तत्व हैं, इन्हीं पर चलकर हम आंतरिक और बाहय रुप से भारत को मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविंद मेनन ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि हम सभी को भाजपा के कायकर्ता होने का गर्व है। स्थापना दिवस पार्टी की नींव का दिन है। नींव के पत्थर को पूजने का दिन है। उन्होंने कहा कि एक–एक कार्यकर्ता आज के दिन यह संकल्प लें कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हम प्राण–प्रण से जुटेंगे।

स्थापना दिवस पर हवन पूजन, पूर्णाहुति के साथ भंडारा संपन्न

भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर समता चौक भोपाल के विशाल परिसर में आध्यात्मिक वातावरण में देश, प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और विकास के लिये हवन पूजन का आयोजन किया गया। हवन पूजन और पूर्णाहूति के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, वरिष्ठ मंत्री बाबूलाल गौर, उमाशंकर गुप्ता, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ध्रुवनारायण सिंह, उषा चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री रामेश्वर शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता विजेश लुनावत, प्रदेश संवाद प्रमुख डॉ. हितेष वाजपेयी, प्रदेश कार्यालय मंत्री आलोक संजर, महापौर कृष्णा गौर, भोपाल जिलाध्यक्ष आलोक शर्मा, नगर निगम के पार्षद, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाद में भंडारा संपन्न हुआ। भंडारा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं, पार्टी हितचिंतकों और जनता ने भाग लिया। भोपाल के सभी 16 मंडलों में जिलाध्यक्ष आलोक शर्मा और जिला पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर पार्टी का ध्वज लगाया और गोष्ठियों में भाग लिया।

इंदौर में स्थापना दिवस पर प्रातः इंदौर भाजपा कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर माखनसिंह चौहान, शंकर ललवानी सहित जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। इंदौर के सभी 11 मंडलों में भाजपा की विचारधारा और विकासयात्रा पर वरिष्ठ नेताओं द्वारा संगोष्ठी में व्याख्यान दिये गये जिसमें वरिष्ठ नेत्री और सांसद सुमित्रा महाजन, अंजू माखीजा, कृष्णमुरारी मोघे ने अपने विचार व्यक्त किए। जबलपुर नगर में पार्टी का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जबलपुर के प्रत्येक बूथों पर यह कार्यक्रम मनाया गया।

मंडलों में विचार गोष्ठियां आयोजित की गयीं। जिसमें प्रदेश महामंत्री राकेश सिंह, ईश्वरदास रोहाणी, सहित जिला पदाधिकारियों ने अपने विचार रखें।

सतना में सभी 12 मंडलों में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पार्टी की विकास यात्रा पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। प्रदेश मंत्री गणेश सिंह, शंकरलाल तिवारी, जिलाध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह बघेल सहित जिला पदाधिकारी मंडलों में आयोजित गोष्ठियों में प्रमुख वक्ता थे।

ग्वालियर में 60 वार्डों में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश शर्मा, महापौर समीक्षा गुप्ता, सहित वरिष्ठ नेताओं ने विचार गोष्ठियों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।

उज्जैन नगर के सभी 9 मंडलों में वक्ताओं ने विचार गोष्ठियों में पार्टी की पंच निष्ठा और विकास यात्रा से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया।

सागर के 23 मंडलों में पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। कार्यकर्ताओं ने घरों पर पार्टी के झंडे लगाए। सभी मंडलों में आयोजित गोष्ठियों में प्रमुख वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विकास यात्रा पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया, सहित जिला पदाधिकारियों ने मंडलों में कार्यक्रम में भाग लिया।

रीवा जिले में सभी ग्राम केन्द्रों, शहर केन्द्रों पर पार्टी का स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने अपने–अपने घरों पर पार्टी का ध्वज लगाया। मंडलों में विचार गोष्ठियां आयोजित की गयी।

रायसेन में सभी जिला पदाधिकारियों ने 11 मंडलों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया। जिला मुख्यालयों पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने बैठक को संबोधित किया। राजगढ़ में प्रदेश उपाध्यक्ष रामपाल सिंह ने कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। सभी 16 मंडलों में जिला पदाधिकारी पहुंचे और कार्यक्रम आयोजित किये गये। छतरपुर में 19 मंडलों में विचार गोष्ठियां आयोजित की गयी।

दमोह जिले में सभी मंडलों में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। मंडलों में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष हेमंत छाबडा सहित जिला पदाधिकारियों ने मंडलों में पहुंचकर पार्टी की रीति नीति से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। टीकमगढ में पार्टी का स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। सभी मंडलों में पार्टी की विकास यात्रा पर संगोष्ठियां आयोजित की गयीं। मुरैना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर अपने अपने घरों में पार्टी के झंडे लगाए। जिला पदाधिकारियों ने सभी मंडलों में पहुंचकर विचार गोष्ठियों में अपने विचार रखे। जिला पदाधिकारी मंडलों में पहुंचे। भिण्ड में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पार्टी ध्वज फहराकर मिष्ठान्न वितरण किया और घर–घर पहुंचकर पार्टी का ध्वज लगाया। सभी मंडलों में विचार गोष्ठियां आयोजित की गयी। अशोकनगर में 9 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया गया और मीसाबंदियों, पूर्व जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया गया। विचार गोष्ठियों में अपने विचार रखे। गुना के सभी 9 मंडलों में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

श्योपुर में कार्यकर्ताओं ने प्रातः प्रभात फेरी निकाली। कार्यकर्ताओं के घरों पर झंडे लगाये। सभी 6 मंडलों के ग्राम केन्द्रों पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। सीहोर जिले के सभी 10 मंडलों में कार्यकर्ताओं ने गोष्ठियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को सुना। बैतूल जिले के 16 मंडलों के 268 ग्राम केन्द्रों पर पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम में आयोजित किया गया। सांसद ज्योति धुर्वे, जिलाध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, विधायक अलकेश आर्य, रतलाम के 14 मंडलों में गोष्ठियां आयोजित की गयी। कार्यकर्ताओं ने घरों पर पार्टी ध्वज लगाये। नरसिंहपुर के 12 मंडलों में कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये। सिवनी में कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकालकर शहर में भ्रमण कर घरों पर पार्टी ने ध्वज लगाये। मंडला में जिला कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। 12 मंडलों पर कार्यक्रम आयोजित किये गये।

बालाघाट में जिला कार्यालय पर पार्टी का ध्वज फहराया गया। 13 मंडलों में गोष्ठी आयोजित की गयी। जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे सहित जिला पदाधिकारियों ने गोष्ठियों में भाग लिया।

कटनी में बूथ स्तर पर गोष्ठी आयोजित की गयी। देवास में 10 मंडलों के ग्राम और नगर केन्द्र पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। शाजापुर में ग्राम केन्द्रों पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। मंदसौर में मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। धार के 21 मंडलों में वक्ताओं ने विचार गोष्ठियों में पार्टी की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। खरगौन के 15 मंडलों में विचार गोष्ठी के माध्यम से पार्टी की विचार धारा और पंच निष्ठाओं से वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। खण्डवा में मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। गणेश गौशाला स्थान पर गोष्ठी आयोजित की गयी। बडवानी में 15 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिलाध्यक्ष एस वीरा स्वामी सहित जिला पदाधिकारियों ने मंडलों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। सीधी में 8 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये। शहडोल के 8 मंडलों में ग्राम केन्द्र स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किये गये। उमरिया के 6 मंडलों में गोष्ठियां आयोजित की गयी। सिंगरौली के 7 मंडलों में विधायक रामलल्लू बैस, जिलाध्यक्ष रामसुमिरन गुप्ता सहित जिला पदाधिकारियों ने गोष्ठियों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। नीमच में 7 मंडलों में विचार गोष्ठियां आयोजित की गयी। ■